https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'स्वच्छता का आंदोलन अब एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचा है'

वर्ष-13, अंक-19 01-15 अक्टूबर, 2018 (पाक्षिक) ₹20

किसान सम्मलेन, नागौर (राजस्थान)

'किसान समृद्ध तो देश समृद्ध'

'मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया'

'स्वच्छ भारत' मिशन ने कैसे बदली भारत की तस्वीर और बना वैश्विक प्रेरणा

'आयुष्मान भारत' से 50 करोड़ से अधिक नागरिकों को होगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ

नागौर (राजस्थान) में किसान सम्मेलन के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का स्वागत करते राजस्थान भाजपा नेतागण

उदयपुर (राजस्थान) में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की बैठक में अभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

उदयपुर (राजस्थान) में अनुसूचित जनजाति सम्मेलन को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

महबूब नगर (तेलंगाना) में एक जनसभा के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का स्वागत करते तेलंगाना भाजपा नेतागण

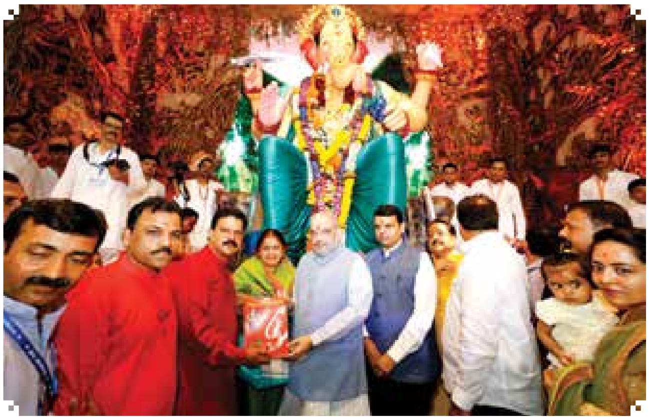

मुंबई में प्रसिद्ध लालबागचा राजा गणपति पंडाल का दर्शन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ नेतागण

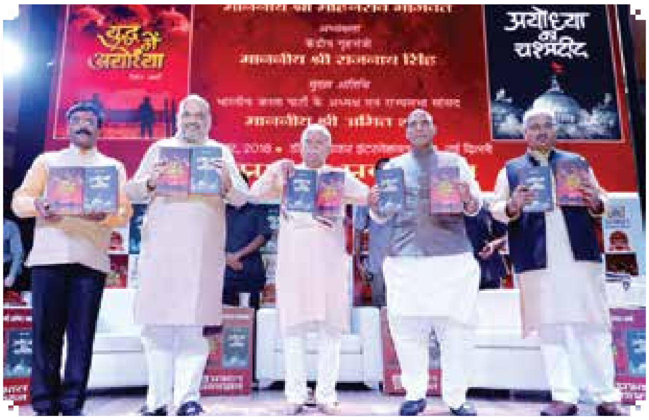

नई दिल्ली में श्री हेमंत शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक 'अयोध्या का चश्मदीद' और 'युद्ध में अयोध्या' के विमोचन के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, रा.स्व. संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह व अन्य

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में किसान को दी जाने वाली राशि को दोगुना किया : अमित शाह**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 19 सितंबर को नागौर में विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान श्री शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब किसानों को...

वैचारिकी

संस्कृति और समाज	12

श्रद्धांजलि

पं.दीनदयाल उपाध्याय	14

लेख

प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने का सबसे श्रेष्ठ...	17
'स्वच्छ भारत' मिशन ने कैसे बदली भारत की तस्वीर और बना वैश्विक प्रेरणा	22
'आयुष्मान भारत' से 50 करोड़ से अधिक नागरिकों को होगा...	24
जनजातीय समाज के समग्र विकास की अभिनव पहल	26

अन्य

आयकर रिटर्न दाखिल करने में 71 प्रतिशत की वृद्धि	10
'स्वच्छता का आंदोलन अब एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचा है'	15
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा कार्य	19
'मोदीजी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए 'सबका साथ, सबका...	21
भाजपा ने त्रिपुरा में 96 प्रतिशत पंचायत सीटें निर्विरोध जीतीं	25
भाजपा ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का एक नया विचार देश...	28
मन की बात	31
अटल काव्यांजलि कार्यक्रम	32

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से	04
व्यंग्य चित्र	04

07 'मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 सितंबर को बांगड़ कॉलेज...

08 'भाजपा सरकार किसानों को फसल पर लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देगी'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री...

09 'ट्रिपल तलाक बिल पर सरकार का अध्यादेश एक सराहनीय कदम'

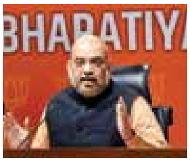

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार...

11 आशाकर्मियों के लाभ पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

देश का हर नागरिक हमारे मेहनतकश किसानों का आभारी है। हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

@AmitShah

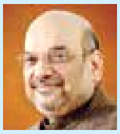

मोदी सरकार की ऐतिहासिक आरोग्य योजना के माध्यम से देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों यानी करीब 50 करोड़ गरीबों को गुणवत्ता वाली 5 लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी।

@Ramlal

महिलाओं का सम्मान दशकों तक राजनीतिक लाभ-हानि का बंधक रहा। उनके आत्मसम्मान तथा जीवन को भयमुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा तीन तलाक बिल के विरुद्ध अध्यादेश पारित। आशा है राजनीतिक लाभ-हानि को छोड़ सभी दलों के सांसद इसको क़ानूनी रूप देने में अपना सहयोग देंगे।

facebook

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसी पहल है, जिसके परिणाम गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाले होंगे। इस योजना के तहत लगभग 10.74 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के फ्री इलाज का कवर प्राप्त होगा।

— भूपेंद्र यादव

किसान भाइयों के हितों के लिए सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है। धान बोनस हेतु कल विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें धान बोनस हेतु 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान भाइयों को बोनस का भुगतान समर्थन मूल्य के साथ करने की राह आसान हो गई है।

—डॉ. रमन सिंह

हमारी सरकार हिमाचल में पर्यटन को पंख लगाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में निर्णय लिया कि "नई राहें नई मंजिलें" योजना के तहत शिमला जिले के चांशल, कांगड़ा जिले में बीड बिलिंग एवं मंडी जिले के जंजैहली को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

— जयराम ठाकुर

व्यंग्य चित्र

वक़्त-वक़्त की बात

बुरा जो देखन मैं चला...

साभार : सोशल मीडिया

तीन तलाक पर अध्यादेश

बेड़ियों से मुक्त हुईं मुस्लिम महिलाएं

'सेकुलरिज्म' के नाम पर कई राजनैतिक दलों द्वारा वोट बैंक राजनीति में लिप्त रहना भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। लंबे समय से 'सेकुलरिज्म' के विकृत रूप को संरक्षण देने के कारण समाज में रूढ़िवादी तत्व हावी हुए हैं। इससे अनेक सामाजिक कुरीतियां 'पर्सनल लॉ' के नाम पर जारी हैं तथा समाज में किसी प्रकार के सुधार में रोड़ा बने हुए हैं। 'सेकुलरिज्म' के नाम पर 'रूढ़िवादी–प्रतिगामी' तत्वों को जिस प्रकार का संरक्षण मिला है, उससे मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बदतर हुई है। उन्हें महिला होने के कारण भेदभाव झेलना पड़ता तो है ही, साथ ही बड़ी संख्या में 'तीन तलाक' जैसी कुप्रथाओं से उनका जीवन बर्बाद हुआ है। दुर्भाग्य से ऐसा तब होता रहा जब भारतीय संविधान में उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त है। तुष्टिकरण एवं वोट बैंक की राजनीति का सबसे भयावह पक्ष यह रहा कि न तो इस संबंध में कभी किसी सुधार को प्रोत्साहित किया गया, न ही इस जैसे मुद्दों को कभी आम बहस के केंद्र में आने दिया गया। अभी तक इन कथित 'सेकुलरिस्ट' दलों के सोच एवं स्वभाव में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है।

'तीन तलाक' पर केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश 2018 एक स्वागत योग्य कदम है। यह अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'तीन तलाक' पर दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के आलोक में लाया गया है। ज्ञातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तीन तलाक को गैरकानूनी एवं असंवैधानिक कहा है। इस अध्यादेश के लागू होने से मुस्लिम पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को किसी भी तरह तीन तलाक दिया जाना अपराध माना जायेगा, जिसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। कोई मुस्लिम महिला इस संबंध में यदि पुलिस को शिकायत करती है तब पुलिस इस पर कार्यवाही करेगी तथा पत्नी एवं उसके बच्चों को गुजारा भत्ता मिलेगा, जिसे परिस्थितियों के अनुरूप दंडाधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। इसे 'कंपाउंडेबल अपराध' की श्रेणी में रखा गया है, ताकि पीड़ित महिला यदि इस संबंध में दंडाधिकारी के समक्ष आवेदन करे, तब समझौते का रास्ता निकल सकता है। इस अध्यादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलेगी, जोकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने के बाद भी इस दंश को झेलने को बाध्य थी।

> इस सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने वाली महिलाओं का साहस अभिनंदनीय है। अपने इस वीरतापूर्ण संघर्ष से उन्होंने न केवल अपनी जंजीरों को तोड़ा, बल्कि मुस्लिम समाज में परिवर्तन एवं सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। मोदी सरकार इनके संघर्षों में अडिग होकर उनके साथ खड़ी रही।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी तीन तलाक पर विधेयक राज्यसभा में अटका हुआ है। वोट बैंक की राजनीति में फंसे कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी दरकिनार करना चाहते हैं। यह वही कांग्रेस है जिसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को धता बताते हुए शाहबानो को न्याय नहीं मिलने दिया था। मुस्लिम समाज में रूढ़िवादी तत्वों के तुष्टिकरण में कांग्रेस इस तरह से अंधी हो चुकी है कि उसे संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी नहीं दिखाई देते और न ही ये मुस्लिम महिलाओं की दुरवस्था ही देख पा रही है। आज जबकि 22 मुस्लिम देश तीन तलाक को किसी न किसी रूप में प्रतिबंधित कर चुके हैं, भारत जैसे 'सेकुलर' देश में न केवल यह जारी था, बल्कि इस पर किसी प्रकार की बहस की भी इजाजत नहीं थी। अनगिनत मुस्लिम महिला जिन्होंने तीन तलाक के दंश को झेला है, उनकी जिंदगी बर्बाद करने तथा हर विवाहित मुस्लिम महिला के सिर पर इसे तलवार की तरह लटकाये रखने की जिम्मेदारी से कांग्रेस भाग नहीं सकती।

इस सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने वाली महिलाओं का साहस अभिनंदनीय है। अपने इस वीरतापूर्ण संघर्ष से उन्होंने न केवल अपनी जंजीरों को तोड़ा, बल्कि मुस्लिम समाज में परिवर्तन एवं सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इनके संघर्षों में अडिग होकर उनके साथ खड़ी रही और वोट–बैंक की राजनीति की जद से उन्हें आजाद किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल्यों की रक्षा तथा महिलाओं को न्याय दिलाने के उसके संकल्प से देश के राजनैतिक विमर्श में सकारात्मक परिवर्तन आया है। परन्तु चिंता का विषय यह है कि कांग्रेस अब भी वोट–बैंक की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही है। क्या केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तीन तलाक की कुप्रथा समाप्त हो जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि सरकार की तीन तलाक रोकने के लिए छह महीने के अंदर कानून बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया। राज्यसभा में इसने इस विधेयक को अटका रखा है। इससे कांग्रेस बेनकाब हुई है। यह अब वोट–बैंक से ऊपर उठने की अपनी इच्छाशक्ति खो चुकी है, फलतः देश की जनता का विश्वास भी इस पर से उठ चुका है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

संगठनात्मक गतिविधियां किसान सम्मलेन, नागौर (राजस्थान)

मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में किसान को दी जाने वाली राशि को दोगुना किया : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 19 सितंबर को नागौर में विशाल किसान सम्मलेन को संबोधित किया। इस दौरान श्री शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब किसानों को यूरिया लेने के लिए लाठी खानी पड़ती थी और यूरिया की कालाबाजारी की जाती थी, लेकिन मोदी सरकार ने यूरिया की नीम कोटिंग करके कालाबाजारी को बंद किया। मोदी सरकार ने किसानों को यूरिया देने का काम किया है।

सम्मेलन के दौरान श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा 'किसान समृद्ध तो देश समृद्ध' का मंत्र लेकर चली है। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेन्द्र मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया था कि केंद्र में बनने वाली देश के किसानों के प्रति समर्पित होगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने केंद्रीय बजट में किसान को दी जाने वाली राशि को भी दोगुना किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी से सवाल पूछा कि यूपीए सरकार ने बजट में किसानों के लिए कितनी राशि आवंटित की थी। श्री अमित शाह ने भाजपा शासित राज्यों में किसानों को दिए जाने वाले लाभ को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि देश में जिन-जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां कृषि विकास दर दहाई अंकों में रहा है जबकि कांग्रेस की सरकारों में यह काफी कम है।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र में 10 सालों तक चलने वाली सोनिया-मनमोहन-राहुल गांधी की यूपीए सरकार के दौरान देश की कृषि विकास दर ऋणात्मक थी, जबकि पिछले चार सालों में कृषि विकास दर 4% से अधिक पहुंचा है। अगर कांग्रेस की सरकारों ने आजादी के 70 सालों में किसानों की भलाई के लिए काम किया होता तो आज भारतीय किसान विश्व के सबसे समृद्ध किसान होते। हमारे दिल में किसानों के लिए दर्द है और उनकी भलाई के लिए काम करने का जज्बा है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसकी प्राप्ति के लिए मजबूत कदम उठाते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का निर्णय लिया है। भाजपा की वसुंधरा सरकार राजस्थान में किसानों को कृषि के लिए ब्याज मुक्त ऋण मुहैया करा रही है। इतना ही नहीं, वसुंधरा सरकार ने किसानों के 50,000 रुपये तक के कर्ज को भी माफ़ कर दिया है, जिससे राज्य के लाखों किसानों को फायदा पहुंचेगा।"

श्री अमित शाह ने अपने सम्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के भी फायदे गिनाये। उन्होंने कहा, "खेतों को पानी पहुंचाने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपये के बजट की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के साथ-साथ नहरों और बांधों पर काम चल रहा है, जबकि वसुंधरा सरकार ने अलग से 44,000 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान नहर सिंचाई योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नारे, चुनावी नारे नहीं होते, हम इसे हकीकत में बदलना जानते हैं और हमने ऐसा करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए खड़ी और एवं उनके उत्थान के लिए संकल्पित है।"

किसानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की सुरक्षा की नहीं, बल्कि अपने वोट बैंक की चिंता है। कांग्रेस पार्टी न तो किसानों का भला कर सकती है और न ही देश की सुरक्षा ही कर सकती है। वह 'जय जवान, जय किसान' के मंत्र को जमीन पर लागू ही नहीं कर सकती। ■

'पिछड़ा वर्ग के करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 सितंबर को बांगड़ कॉलेज, पाली (नगर चौराहा के पास) में जोधपुर संभाग स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और ओबीसी समाज की अनदेखी करने के लिए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इससे पहले उन्होंने अणुवृत नगर, पाली (रामलीला मैदान के पास) में तीन जिलों पाली, जालौर और सिरोही (14 विधानसभाओं) और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर (नगर निगम के पास) में तीन अन्य जिलों जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर (19 विधानसभाओं) के शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर में जोधपुर संभाग स्तरीय युवा सम्मेलन को भी संबोधित किया।

श्री शाह ने कहा कि राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने ओबीसी समुदाय की सभी जातियों को सत्ता में भागीदारी देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति अथवा समाज की पार्टी नहीं, बल्कि सभी जातियों और समाज का सुगंधित पुष्पगुच्छ है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के पिछड़ा समाज के कल्याण के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि 1955 से देश के पिछड़े वर्ग के लोग पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करते रहे, लेकिन 55 साल से अधिक समय तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस सरकार इसे अनदेखा करती रही। उन्होंने कहा कि जब पिछड़े घर में जन्म लेने वाले श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक योजना का सबसे ज्यादा लाभ पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला है, जो अब खुद का स्वरोजगार कर सकते हैं और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है, गरीब और पिछड़ों के लिए बैंक के दरवाजे खोले गए हैं, जन-धन योजना के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट खोले गए हैं और दो करोड़ लोगों को घर और बिजली देने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मिशन इन्द्रधनुष योजना के तहत देश के 18 करोड़ गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराया गया है, लेकिन कांग्रेस को कभी इन बातों का ध्यान नहीं आया।

> 55 साल से अधिक समय तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस सरकार अनदेखा करती रही। जब पिछड़े घर में जन्म लेने वाले श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया।

श्री शाह ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीबों को सिर्फ 5 रुपये में सुबह का नाश्ता और केवल 8 रुपये में दोपहर के भोजन का प्रबंध किया है। इतना ही नहीं वसुंधरा सरकार ने राज्य के किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्ज भी माफ़ किया है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस ने 55 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, राजस्थान में भी वर्षों तक शासन किया, लेकिन आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को गरीब की भूख का अहसास नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने गरीबों के लिए केंद्र सरकार के अलावे 35 लाख और घरों का निर्माण किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आने वाला है, कांग्रेस फिर से विकास पर बात करने के बजाय जाति-पाति, अगड़े-पिछड़े और तुष्टीकरण की राजनीति का राग अलापने वाली है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के इन हथकंडों को बखूबी जानती है और वह आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका करारा जवाब देगी। ■

'भाजपा सरकार किसानों को फसल पर लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देगी'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 15 सितंबर को तेलंगाना के महबूब नगर में आयोजित ऐतिहासिक जनसभा 'BJP Shankaravam' को संबोधित किया और राज्य की जनता से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की अपील की।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सारे देश में लोक सभा और विधान सभा चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं, ताकि खर्च कम हो और सभी राज्य प्रगति के पथ पर एक समान आगे बढ़ें लेकिन तेलंगाना में तो लोक सभा के चुनाव के साथ ही विधान सभा चुनाव होने थे, जिसे हार के डर से टीआरएस 9 महीने पहले कराना चाहती है। टीआरएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्या चंद्रशेखर राव जी को मई में लोक सभा चुनाव के साथ चुनाव होने पर जीतने का विश्वास नहीं था क्या? यदि मई में टीआरएस को जीत का भरोसा नहीं था तो इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में भी चुनाव कराने से भी तेलंगाना में टीआरएस की सरकार नहीं बनने वाली।

श्री शाह ने कहा कि तेलंगाना राज्य और तेलुगु अस्मिता का सवाल लंबे समय से जनता उठाती रही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रजाकारों के भयानक जुल्म के खिलाफ यहां की जनता ने जो बलिदान दिया, उनके सम्मान में 17 सितंबर को प्रति वर्ष 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' मनाया जाता है, लेकिन एआईएमआईएम और ओवैसी के डर से टीआरएस सरकार ने 17 सितंबर को 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' मनाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी एआईएमआईएम और ओवैसी के डर 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' मनाना बंद कर दे, वह पार्टी तेलंगाना के अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने तेलंगाना की जनता को वचन देते हुए कहा कि आप राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइये, हम प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' का भव्य कार्यक्रम मनाएंगे।

श्री शाह ने कहा कि टीआरएस एक नया झूठा शिगूफा छोड़ रही है कि ओवैसी की पार्टी से उसका कोई गठजोड़ नहीं है, जबकि दोनों आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि ओवैसी की पार्टी से टीआरएस का कोई लेना-देना नहीं है तो फिर टीआरएस सरकार किसके डर से और किसके कहने पर अल्पसंख्यकों को अलग से 12% आरक्षण देने का प्रस्ताव लाई? उन्होंने कहा कि टीआरएस सरकार ये अल्पसंख्यकों को 12% अलग से आरक्षण देगी कहां से जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता। इस स्थिति में तेलंगाना की टीआरएस सरकार तो एससी/एसटी, ओबीसी और आदिवासियों के आरक्षण

को काट कर ही दे सकती है। यदि टीआरएस सरकार अल्पसंख्यकों को अलग से 12% आरक्षण देना चाहती है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि किसका आरक्षण ख़त्म कर वह ये आरक्षण देना चाहती है?

श्री शाह ने कहा कि तेलंगाना की केसीआर सरकार 2014 में किये गए अपने वादे पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में केसीआर ने बहुमत मिलने पर तेलंगाना को दलित मुख्यमंत्री देने का वादा किया था लेकिन जब पूर्ण बहुमत मिला तो वे वादे से पलट गए और खुद ही मुख्यमंत्री बन बैठे। यह तेलंगाना के दलित समाज के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 2014 में एक दलित को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, लेकिन आप ये बताइये कि आप 2018 में दलित को मुख्यमंत्री बनायेंगे या नहीं? उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जिस तरह से दलित समाज पर अत्याचार हुआ है, उससे दलित समाज में टीआरएस सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं तेलंगाना की जनता को आश्वस्त करते हुए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे तेलंगाना का निर्माण करेगी, जहां न तो दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार होगा और न ही किसानों पर गोलियां चलाई जायेंगी, न ही उन्हें हथकड़ियां पहनाई जायेंगी। उन्होंने कहा कि एक आंकड़े के अनुसार पिछले साढ़े चार सालों में तेलंगाना में 4200 से अधिक किसान आत्महत्या करने को विवश हुए हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि एक ओर टीआरएस सरकार की गलत नीतियों के कारण तेलंगाना में किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों को उनके फसल पर लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है। ■

एक ओर टीआरएस सरकार की गलत नीतियों के कारण तेलंगाना में किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों को उनके फसल पर लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है।

केंद्र ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के अध्यादेश को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 सितंबर को एक बार में तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अध्यादेश के बारे में केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अपराध को संज्ञेय बनाने के लिए किसी महिला या उसके सगे रिश्तेदार को किसी पुलिस थाने में केस दाखिल करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध के मामलों में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष समझौता भी हो सकता है, बशर्ते प्रभावित महिला इसके लिए सहमत हो।

कानून मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से तीन तलाक की कुप्रथा पर पाबंदी लगाए जाने के बाद भी यह जारी है, जिसके कारण अध्यादेश लागू करने की आवश्यकता पड़ी। श्री प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्यसभा में लंबित 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक' को पारित करने में सहयोग नहीं कर रही है। श्री प्रसाद ने कहा कि यह मेरा गंभीर आरोप है कि एक महिला की ओर से कांग्रेस की अगुवाई किए जाने के बाद भी उन्होंने विधेयक का समर्थन नहीं किया।

तीन तलाक की प्रथा को ''बर्बर और अमानवीय'' करार देते हुए उन्होंने कहा कि करीब 22 देशों ने तीन तलाक का नियमन किया है। जबकि वोट बैंक की राजनीति के कारण भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में लैंगिक न्याय की पूरी अनदेखी की गई। उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, ''मैं सोनिया जी से एक बार फिर अपील करूंगा कि लैंगिक न्याय के लिए देशहित में यह अध्यादेश लाया गया है। मैं आपसे अपील करता हूं कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के न्याय के हित में इसे पारित करने में मदद करें।''

गौरतलब है कि तीन तलाक पर मूल विधेयक को लोकसभा द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और यह राज्यसभा में लंबित है, जहां भाजपानीत राजग के पास बहुमत नहीं है। ■

ट्रिपल तलाक बिल पर सरकार का अध्यादेश एक सराहनीय कदम: अमित शाह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा तीन तलाक की कुप्रथा पर अध्यादेश को कैबिनेट द्वारा मंजूरी देने के ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करता हूं। इस निर्णय से मोदी सरकार ने देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप बने तीन तलाक से उन्हें मुक्ति देकर समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया है।

श्री शाह ने कहा कि यह अध्यादेश उन सभी राजनीतिक दलों के लिए भी एक आत्मग्लानि एवं आत्मचिंतन का विषय है, जिन्होंने अपनी वोटबैंक की राजनीति के लिए दशकों से मुस्लिम समाज की महिलाओं को इस कुप्रथा से प्रताड़ित होने को मजबूर किया। यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। यह मुस्लिम महिलाओं के जीवन में आशा और सम्मान का नया युग लाएगा।

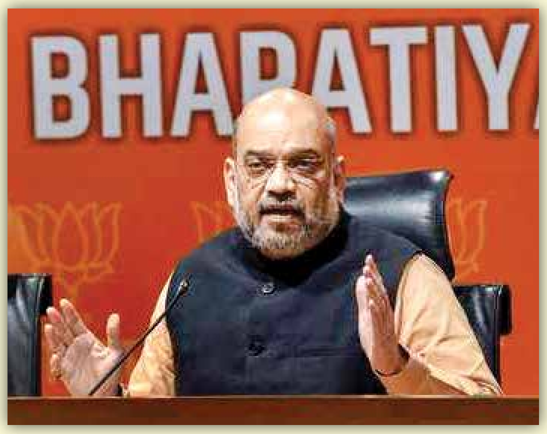

उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल पर सरकार का अध्यादेश एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाओं के समानता और मूलभूत संवैधानिक अधिकारों की जीत सुनिश्चित हुई है। पार्टी मुस्लिम महिलाओं को मिले उनके अधिकारों एवं सम्मान का स्वागत करती है तथा इसे संकल्पवान 'न्यू इंडिया' के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार महिलाओं के सम्मान व उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कृतसंकल्पित है। हमारा स्पष्ट मानना है कि धर्म अथवा सम्प्रदाय के आधार पर मुस्लिम माताओं-बहनों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।

ज्ञात हो कि ट्रिपल तलाक बिल - द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल, 2017 लोक सभा से पहले ही पास हो चुका है, जबकि कांग्रेस पार्टी के दोहरे रवैये, विरोध और महिला विरोधी मानसिकता के कारण राज्य सभा में यह विधेयक पास नहीं हो सका, जिसके कारण सरकार को मुस्लिम महिलाओं के अधिकार व सम्मान की रक्षा के लिए अध्यादेश लाना पड़ा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 19 सितंबर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यूएस) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएचएस) का मानदेय बढ़ाने तथा आंगनवाड़ी सेवाओं (समेकित बाल विकास सेवा अम्ब्रेला स्कीम) के तहत आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कार्य निष्पादन के अनुरुप प्रोत्साहन राशि दिए जाने को मंजूरी दे दी। इसके लिए 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में कुल 10649.41 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।

मानदेय बढ़ाए जाने से करीब 27 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। आंगनवाड़ी सेवा (अंब्रेला आईसीडीएस) योजना एक वृहत योजना है जिसके तहत देशभर में एडब्ल्यूसी/गांव स्तर के लाभार्थी हैं। बढ़ा हुआ मानदेय निम्न हैः

कार्यकर्ताओं की श्रेणी	पुरानी दरें /प्रति माह	संशोधित दरें/ प्रति माह
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	3000/-रुपये	4500/- रुपये
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (मिनी-एडब्ल्यूसी)	2250/- रुपये	3500/- रुपये
आंगनवाड़ी सहायिका	1500/- रुपये	2250/- रुपये (*)

(*)आंगनवाड़ी केन्द्रों के बेहतर संचालन के लिए कार्यप्रदर्शन के हिसाब से आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिमाह 250/- रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के भुगतान को भी मंजूरी दी गयी है।

मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी होगी

प्रभाव : इससे नवजात शिशुओं में कुपोषण और रक्त अल्पता तथा जन्म के समय कम वजन जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी, किशोरवय बालिकाओं का सशक्तिकरण, कानूनी मामलों में उलझे बच्चों को सुरक्षा उपलब्ध कराने और कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए सुरक्षित स्थान भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इसके अलावा लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए संबंधित मंत्रालयों तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच समन्वय तथा उन्हें सही दिशा-निर्देश जारी करने और उनके प्रदर्शन पर निगरानी रखने की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा सकेगा।

पृष्ठभूमि : बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) का उद्देश्य छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। इस योजना के लाभार्थियों में इन बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भी शामिल हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिये जाने वाले मानदेय में पिछली बढ़ोतरी 2011 में की गई थी। जीवन यापन तथा बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार के खर्चों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए मानदेय में 2017 में भी वृद्धि की गई थी। ■

आयकर रिटर्न दाखिल करने में 71 प्रतिशत की वृद्धि

वित्त वर्ष 2018 के दौरान (दाखिल करने के लिए 31 अगस्त, 2018 तक बढ़ाई गई नियत तिथि) दाखिल किए गए आयकर रिटर्न (आईटीआर) की संख्या में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 31 अगस्त, 2018 तक 'ई-फाइल' आईटीआर की कुल संख्या 31 अगस्त, 2017 तक के 3.17 करोड़ की तुलना में 5.42 करोड़ आंकी गई, जो 70.86 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। 31 अगस्त 2018, जो आईटीआर दाखिल करने के लिए बढ़ाई गई अंतिम तिथि थी, को लगभग 34.95 लाख रिटर्न अपलोड किए गए।

दो श्रेणियों में आईटीआर की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इन श्रेणियों के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों (आईटीआर-1 एवं 2) द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या के साथ-साथ अनुमानित कराधान योजना (आईटीआर-4) का लाभ उठाने वाले लोगों द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है।

31 अगस्त, 2018 तक वेतनभोगी व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए ई-रिटर्न की कुल संख्या वित्त वर्ष 2017 की इसी अवधि के दौरान दाखिल किए गए 2.19 करोड़ रिटर्न की तुलना में 3.37 करोड़ आंकी गई, जो रिटर्न की कुल संख्या में 1.18 करोड़ अथवा 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

'अनुमानित कर योजना' का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों द्वारा 31 अगस्त, 2018 तक दाखिल किए गए ई-रिटर्न की कुल संख्या 31 अगस्त, 2017 तक दाखिल किए गए 14.93 लाख रिटर्न की तुलना में 1.17 करोड़ आंकी गई, जो रिटर्न की कुल संख्या में 681.69 प्रतिशत की दमदार वृद्धि दर्शाती है। ■

आशाकर्मियों के लाभ पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 19 सितंबर को आशाकर्मियों के लाभ पैकेज को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। ये पैकेज अक्टूबर 2018 से प्रभावी होगा। इसका भुगतान दो अलग मदों के तहत नवम्बर 2018 से किया जाएगा।

इस पैकेज की लाभार्थी के रूप में उन आशाकर्मियों और आशा सहायिकाओं को नामित किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए सभी पात्रताएं पूरी करती हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशाकर्मियों को मिलने वाली नियमित राशि और प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह किया गया है। इस पैकेज के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 2018-19 और 2019-20 की अवधि में किया जाने वाला भुगतान 1,224.97 करोड़ रुपये होगा।

लाभार्थियों की संख्या

- अनुमानित एक करोड़ छह लाख छत्तीस हजार सात सौ एक आशाकर्मी और आशा सहायिकाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दायरे में आएंगी।
- अनुमानित नौ लाख सत्तावन हजार तीन सौ तीन आशाकर्मी और आशा सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
- अनुमानित दस लाख बाईस हजार दो सौ पैंसठ आशाकर्मियों को नियमित गतिविधियों के लिए मौजूदा एक हजार रुपये के स्थान पर न्यूनतम दो हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे।

विवरण

आशाकर्मी और आशा सहायिकाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की लाभार्थी होंगी। योजना के लिए तय शर्तों के मुताबिक इसका लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु वाली महिलाएं ले सकेंगी। बीमा की अवधि एक वर्ष की (1 जून से 31 मई) होगी। बीमा के तहत मिलने वाले लाभ निम्न हैं–

- दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर दो लाख रुपये का भुगतान।
- दोनों आंखें, दोनों हाथ, दोनों पैर या एक हाथ और एक पैर पूरी तरह खराब हो जाने तथा एक आंख की रोशनी पूरी तरह चले जाने की स्थिति में दो लाख रुपये का भुगतान।
- एक आंख की रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाने या एक पैर और एक हाथ पूरी तरह खराब हो जाने की स्थिति में एक लाख रुपये का भुगतान।
- केन्द्र सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी 12 रुपये की प्रीमियम राशि हर साल दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (दुर्घटना बीमा) का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु की उन आशाकर्मियों और आशा सहायिकाओं को मिलेगा, जो इसके लिए सभी पात्रताएं पूरी करती हैं। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार की ओर से सालाना औसतन 330 रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाएगा। बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की होगी। किसी कारणवश मृत्यु हो जाने पर लाभार्थी को दो लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
- आशाकर्मियों को नियमित कार्यों के लिए प्रति माह मौजूदा एक हजार रुपये के स्थान पर दो हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह राशि केन्द्र और राज्य स्तर पर अनुमोदित कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होगी। आशा लाभार्थी पैकेज के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मौजूदा संस्थागत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा।

लक्ष्य

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक 65 प्रतिशत आशाकर्मियों और आशा सहायिकाओं को पंजीकृत किया जाना।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 30 अक्टूबर, 2019 तक 100 प्रतिशत आशाकर्मियों और आशा सहायिकाओं को पंजीकृत किया जाना।
- नियमित गतिविधियों के लिए तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में आशाकर्मियों को अक्टूबर से बढ़ी हुई दर से प्रति माह दो हजार रुपये का भुगतान। यह भुगतान नवम्बर 2018 से किया जाएगा। ■

संस्कृति और समाज

दीनदयाल उपाध्याय

गतांक का शेष...

संघ के काम में वह चीज़ अपने आप आती है। इसलिए हमने वहीं पर इस बात पर जोर दिया कि हम संघ का कार्य निस्स्वार्थ बुद्धि से करेंगे। प्रामाणिकता और निस्स्वार्थ बुद्धि हमें धोखा दे जाती है। आदमी को अपने आपको जैसे जब लगता है कि मानो हम निस्स्वार्थ हैं, पर वास्तव में निस्स्वार्थ होते नहीं। कहीं-कहीं मन के अंदर स्वार्थ छिपा रहता है। इसलिए वह छिपा हुआ स्वार्थ कहीं आ न जाए, उसके लिए अपने पास प्रामाणिकता है। प्रामाणिकता अपने मन में रहे और तब तक यह संघ का काम करेंगे। ये चीजें स्वतः प्रकट होती हैं, जब संघ की शाखा हम चलाते हैं। उदाहरण के लिए अच्छी शाखा में काम करने वाले स्वयंसेवकों के गुणों का विचार, स्वयंसेवक में कौन-कौन से गुण चाहिए, इसका विचार करना तो शायद भारतीय संस्कृति के विशेष लक्षण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि अपनी शाखा में किसी भी स्वयंसेवक को यह नहीं कहते कि हम क्यों आते हैं, क्या सोचकर आते हैं, हमारे सामने कौन सा विचार आता है। हमारे सामने, हम हिंदू हैं, इसका भी विचार आता है। हिंदू संगठन करेंगे, गौरव से रहेंगे, सामर्थ्य के साथ रहेंगे। सामूहिक भाव से रहेंगे, फिर मैं इतना ऊंचा उठूगा, मैं यह स्थान प्राप्त करूंगा, समाज के अंदर मेरा इतना ऊंचा स्थान हो जाएगा, समाज के दस लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, मेरी जयकार होगी-यह सोचकर शाखा पर नहीं आते।

कोई भी यह विचार नहीं करता कि कल ईरान के ऊपर आक्रमण करेंगे, परसों अफगानिस्तान के ऊपर, इसके बाद रूस के ऊपर अपना आधिपत्य जमाएंगे और इस तरह की बातें करने के लिए शाखा पर नहीं जाते हैं। दूसरों को गुलाम बनाने के लिए शाखा पर नहीं जाते हैं। हम अपने अंदर निस्वार्थ भाव लेकर एक हिंदू के नाते संसार में सुख के साथ शांति से विचार करने के लिए शाखा पर जाते हैं। हिंदू के नाते से हम सोचते हैं कि वह क्यों आया है, इसके जीवन के साथ इस प्रकार से एकरूप हो जाएं इसका हम बराबर विचार करते हैं। यानी दूसरे स्वयंसेवक के जीवन के साथ एकरूप हो जाएं, इस बात का बराबर विचार, लोक-संग्रह का हमेशा यही विचार रखा कि लोगों को इकट्ठा कैसे करेंगे, लोगों के साथ एकरूप होकर जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित करके, उनकी सेवा करके, उनको सुखी बनाकर कैसे अपनी ओर आकृष्ट करेंगे इस बात की चिंता करते हुए कार्य करते चले जाना है।

इसमें कोई स्वार्थ नहीं, हिंदू के नाते, उसके लिए हम बराबर जो काम करते चले जाते हैं, इससे दूसरे के जीवन के साथ एकात्मता आती है। हमारे तुम्हारे अंदर से भी एक वही भगवान् बोल रहा है। वही एक सत्य उद्भाषित हो सकता है, जो मेरे अंदर है। इस नाते से यह विचार जब हम करते हैं कि जो शाखा में आता है, वह भी स्वयंसेवक है और वह भी स्वयंसेवक है, जो निस्स्वार्थ बुद्धि से काम कर रहा है। उसके कहने में, विचारों में, मन में भी सत्य हो सकता है। वह सत्य का जो सारा ठेका है, वह मेरे पास ही नहीं है, जिस निस्स्वार्थ बुद्धि से मैं काम करता हूं और मेरे अंदर कोई विचार आता है। इतना ही विचार उसके अंदर भी निस्वार्थ बुद्धि से काम करने से आता है। इसलिए उसके विचारों के प्रति आदर का भाव रखते हुए यह दृष्टि स्वयं प्राप्त होती है। यह सहिष्णुता की वृत्ति संघ के स्वयंसेवक के अंदर होती है। फिर वह इसके साथ एकरूप होता है। इस सहिष्णुता के साथ-साथ सेवा की भी वृत्ति आती है। उसके साथ सेवा करना, किसी को सुख देना, आनंद मानना-यह सेवा का भाव रखता है।

वह किसी भी बीमार स्वयंसेवक के पास यह सोचकर नहीं जाता कि आज वह बीमार है, कल जब मैं बीमार पड़ेगा तो वह मुझे देखने आएगा। इस प्रकार का विचार उसके मन में नहीं आता। वह तो यही सोचकर जाता है कि उसे जाना चाहिए। जब वह स्वयं बीमार हुआ तो उसे इस बात की भी चिंता या शिकायत नहीं रहती कि कोई उसे देखने क्यों नहीं आया। वह ऐसा भी नहीं सोचता कि एकात्मता आती है तो स्वाभाविक है, बहुत से गुण हमारे अंदर आते हैं। दूसरे, अपने जीवन के अंदर आत्मीयता का भाव लाकर पहली बात तो यही आती है कि उसके बारे में एक बड़ी सहनशीलता की भावना पैदा हो जाती है। वही सहनशीलता उसकी अच्छाई-बुराई जो कुछ भी है, उसे सहने के हम आदी बन जाते हैं। हम कठोर होकर उसको चार गालियां नहीं सुनाते, जिसके साथ एकरूप होना चाहते हैं। हमारे मन में सहिष्णुता आती है। यह सहिष्णुता स्वयंसेवकों के लिए नितांत आवश्यक है, कई बार हम यह भूल जाते हैं। हम ऐसा समझने लगते हैं कि उसे संघ का पता नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं, उसे दुनिया का पता नहीं-ऐसा नहीं है, वरन् हम यह मानकर चलते हैं कि भाई उसे संघ का पता है। उसकी बात हम सुनते हैं। उसमें कुछ सच्चाई है। उस सच्चाई को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसको सामने रखते हैं। जहां दोनों के बीच सहिष्णुता का भाव रहता है, वहां पर यह कठिनाई नहीं होती है। यदि दोनों के भिन्न विचार रहे तो भी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। इस प्रकार की सहिष्णुता का भाव संघ के स्वयंसेवक में आता है। अपनी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, वह है सहिष्णुता।

पाश्चात्य संस्कृति में यह कहीं नहीं दिखाई देती। किसी स्वयंसेवक के मन में यह नहीं आता कि मैंने संघ के कारण अपना घर-बार छोड़ दिया और संघ ने मुझे क्या दिया? उसके मन में अपेक्षा भी नहीं होती कि संघ के स्वयंसेवक आकर उसका काम करें, क्योंकि उसने संघ का काम इसलिए नहीं किया कि उसकी कोई मदद करनेवाला हो। उसने तो निस्स्वार्थ बुद्धि से काम किया। यदि उस बीमार स्वयंसेवक को कोई चार स्वयंसेवक देखने भी आते हैं, तो वह उनसे यही कहता है कि अरे, तुम लोग अपना समय क्यों ख़राब करते हो? जाओ, देखो कि शाखा में और कौन-कौन आए हैं और कौन-कौन

नहीं आए। उसके मन में तो चिंता का ही भाव पैदा होता है, किसी अपेक्षा का नहीं। जहां पर प्रतिफल का भाव आ जाए, वह सेवा नहीं है। सेवा में से ही एक दूसरा भाव आता है, जिसे हम कर्तव्य का भाव कहते हैं। वहां अधिकार का भाव नहीं आता। कर्तव्य इस नाते से करता है कि यह मेरा काम है, मुझे करना चाहिए। यह मेरा अधिकार नहीं है। हमारी भाषा में अधिकार का अर्थ भी कर्तव्य के रूप में ही किया है। पुत्र का अधिकार है कि पिता की सेवा करे, पिता का अधिकार है कि पुत्र का पालन करे। यह अधिकार इसी रूप में प्रयोग हुआ, जिस अर्थ में हम कर्तव्य करते हैं। अधिकार इस अर्थ में शायद हमारे यहां प्रयोग नहीं हुआ। यह हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। हम देखते हैं कि अपनी शाखा में भी उस अधिकार की कल्पना नहीं आती। स्वयंसेवक भी उस नाते से कभी विचार नहीं करता। वह कर्तव्य के नाते से करता चला जाता है। कोई दूसरा स्वयंसेवक नाराज हो गया तो वह यह नहीं सोचता कि वह मुझसे माफ़ी मांगे, उसने यदि गाली दी तो भी वह यह नहीं सोचता कि वह अपनी ग़लती के लिए माफ़ी मांगे। वह तो सोचता है कि यदि किसी स्वयंसेवक ने कोई बात कह दी तो यह सिर्फ मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके पास जाकर उसके गुस्से को शांत करूं, उसे समझाऊं। वह माफ़ी मंगवाने के लिए नहीं, बल्कि माफ़ी मांगने के लिए जाता है।

यह वही वृत्ति है, जिसके बारे में कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि' जब परीक्षा लेने गए तो उन्होंने विष्णु को लात मारी, लेकिन भगवान् विष्णु उनका पैर पकड़कर सहलाने लगे और बोले, 'मेरा वक्ष स्थल कितना कठोर है, आपको तो पीड़ा पहुंची होगी।' यह जो भाव है, यही बताता है कि जहां पर निस्वार्थ वृत्ति से काम करने की प्रवृत्ति होती है, वहां पर यह भाव स्वाभाविक रूप से आएगा कि अपने अंदर के जिस आधार पर खड़े हुए हैं, वह एक तपस्या का भाव है।

तपस्या के काम तो जीवन में सभी प्रकार के होते हैं। मेहनत, मज़दूरी, परिश्रम और तपस्या में अंतर होता है। जहां एक उदात्त ध्येय लेकर निस्वार्थ बुद्धि से काम किया जाता है, उसे हम तपस्या कहते हैं। कुछ भी काम करते रहते हैं, उसे परिश्रम कहते हैं। हम यहां पर परिश्रम नहीं, तपस्या करने चले हैं। तपस्या का भाव जीवन में आता है और इसलिए यह जो तपस्या है, वह आजीवन चलती है। जन्म-जन्मांतर तक चलती जाती है। इस प्रकार की तपस्या का आधार लेकर संघ में प्रविष्ट हुए हैं। हमारी संस्कृति भी इस प्रकार तपस्या के आधार पर खड़ी है। हमारा जीवन भारत में तपस्या के लिए पैदा होता है, मेहनत-मज़दूरी के लिए नहीं, भोग के लिए पैदा नहीं होता।

भोग के आधार पर हमने कल्पना नहीं की। हम तो यहां पर एक यज्ञ करने आते हैं। तपस्वी एवं जोगी का जीवन व्यतीत करने आते हैं। तपस्वी कर्मयोगी का जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं। एक व्रत का पालन करते चले जा रहे हैं। यदि इस आधार पर हम देखें, प्रचार करें कि हमारी संस्कृति के जो-जो भी लक्षण हैं-कर्तव्य-भावना, सेवा, सहिष्णुता-यहां पर ये सारी चीजें होंगी। ये चीजें दूसरे के जीवन के साथ एकरूप होकर आत्मीयता के आधार पर खड़ी हैं। सेवा की भावना होगी, सहयोग की भावना होगी, व्यक्ति संयम करना सीखेगा। यहां पर भोग का आधार न होकर संयम का आधार होगा। संस्कृति की ये सारी चीजें उसकी सारी विशेषताएं हैं।

हमारी संस्कृति में तपस्या का आधार है संस्कृति का संरक्षण। यानी कोई ऐसा संरक्षण नहीं कि चलो भाई आज हम संगठन कर रहे हैं और जिस दिन दस लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो रूट मार्च निकालेंगे, अपितु यहां पर स्वाभाविकता से संयम की बात सीख लेंगे। और फिर वहां जाकर जब संस्कृति के ऊपर हमला होगा तो रक्षण के लिए खड़े हो जाएंगे। चारों ओर से व्यूह बनाकर खड़े हो जाएंगे कि आओ, जिसको आना है, कौन आता है। यह कार्य संस्कृति का संरक्षण नहीं। इसलिए जब हमने कहा कि हम संस्कृति का संरक्षण करते हैं तो हमारे अपने जीवन के अंदर कर्म का भाव आता है और इसको छोड़कर हम भोग की भावना के आधार पर अपना जीवन पाश्चात्यों की तरह भोग प्रधान नहीं बनाते हैं। हम अपने स्वार्थों की रक्षा करते चले जाएं। व्यापार बुद्धि से ही सब चीज़ सोचते चले जाएं। पैसे की भावना से, यश की भावना से कुछ पदवी की कामना से ही कार्य करें, ऐसा नहीं होता है।

अपितु संस्कृति का संरक्षण, इसके माने कुछ और हैं। संस्कृति का संरक्षण न तो व्याख्यानों से होगा, न हमने उसके लिए कोई मोरचा निकाला। हमने संस्कृति के संरक्षण की दृष्टि से भावनाओं की उन बाह्य स्वरूपों की भी चिंता नहीं की। जीवन में कोई ऊंचा पद मिल जाएगा, इसका भी विचार नहीं किया। हमने कहा कि हमारी संस्कृति की जो आत्मा है, मूलमंत्र है, मुख्य-मुख्य चीजें हैं- यदि ये मानव जीवन में बनी रहीं, यह दृष्टि बनी रही तो हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर लेंगे। यह न व्याख्यानों से किया न पुस्तकों से किया।

हम एक विश्वास लेकर खड़े हुए हैं। इसलिए संस्कृति संरक्षण, मेहनत और बाक़ी की चीजों की एवं व्यवस्थाओं की चिंता न करते हुए यह एक मूल चीज़ कैसे आएगी, कैसे प्रगति होगी, इसका ही विचार अपने सामने रखा है तथा यह हमारे व्यवहार में कैसे

आएगी, प्रत्येक स्वयंसेवक इसको जानता नहीं। बाक़ी उसे कैसे व्यवहार में लाना है, इसके लिए एक छोटा सा रास्ता है, जिसमें शिशु स्वयंसेवक भी नए को लाने की सोचता है, नए को लाने की चिंता करता है। उसको फिर अपना मित्र बनाता है। उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह अपने आप इस प्रकार का व्यवहार करता चला जाता है। इस प्रकार के निस्वार्थ भाव से हमने जहां इस बात की चिंता की उसके लिए दस स्वयंसेवक इकट्ठे हो गए और बीस स्वयंसेवक आ गए, इसे शाखा का रास्ता कहते हैं।

इन बीस स्वयंसेवकों का कोई काम आ गया या एक स्वयंसेवक को कोई काम आ गया तो सब वहां पहुंचकर उसका काम करेंगे। काम करते होंगे। यह मैं नहीं कहता, परंतु हमने ऐसा विचार नहीं रखा। हमने यह भी नहीं सोचा कि सामूहिक शक्ति का एक-एक व्यक्ति उपयोग कर लेगा। इसलिए अपना वह पुराना उदाहरण है कि अपने मुख्य शिक्षक की शादी है तो उसमें संघ बैंड का उपयोग नहीं होगा, फिर कहां होगा। परंतु कहा कि संघ बैंड इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगेगा। निस्स्वार्थ बुद्धि बनी रहे, इस वृत्ति का हमने ध्यान रखा है। स्वार्थ बद्धि बैक डोर से भी न आए। टेढ़े तरीके से भी न आ जाए। इसलिए हम शाखाओं का जाल संपूर्ण देश में निस्स्वार्थ बुद्धि के आधार पर फैलाते जाएं और तब हम कहेंगे कि हमारी संस्कृति सुरक्षित है और हमारे साथ हमारी संस्कृति जीवन में प्रविष्ट हो रही है। यह व्यापक आधार पर खड़ी होती चली जाएगी। इस भाव की जितनी हम अभिवृद्धि करेंगे तो हम अपने धर्म, संस्कृति और समाज तीनों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ■ समाप्त

(संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : कानपुर, -जून 4, 1959)

कुशल संगठक व विचारक राजनेता

(25 सितम्बर 1916–11 फ़रवरी 1968)

स्वतंत्र भारत की राजनीति में कुछ ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जो 'विचार और कर्म' दोनों के धनी हों। पं. दीनदयाल उपाध्याय ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो कुशल संगठक तो थे ही साथ ही मौलिक विचारक भी थे। उन्होंने 16 वर्षों तक देशभर में प्रवास करके भारतीय जनसंघ को एक मजबूत संगठन बनाया और साथ ही, 'एकात्ममानव दर्शन' जैसी विचारधारा का प्रतिपादन कर भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय वैचारिक अधिष्ठान भी प्रस्तुत किया।

दीनदयालजी 'सादा जीवन–उच्च विचार' के पुजारी थे। उनकी वेशभूषा सामान्य थी, लेकिन उनके विचार बड़े प्रेरक और प्रखर थे। खद्दर का कुर्ता, धोती, साधारण कैनवास के रबड़ के सोल वाले जूते, मोटा चश्मा, एक सामान्य झोला, जिसमें कुछ किताबें और एक जोड़ी पहनने के कपड़े। आम आदमी की तरह उनकी वेशभूषा थी।

मथुरा जिले के नगला चन्द्रभान ग्राम में 25 सितम्बर 1916 को जन्मे दीनदयालजी ने बचपन से ही विकट परिस्थितियों का सामना किया। ढाई वर्ष की अवस्था में जब वो थे, तो पिता का देहांत हो गया। सात वर्ष के थे तो माता जी का निधन। जब वे नवीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब छोटा भाई शिवदयाल का देहांत। 1935 में नानी चल बसी। 1940 में ममेरी बहन का निधन। मृत्यु ने उन पर निरंतर आघात किए, लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों का मन मजबूत कर सामना किया।

दीनदयालजी पढ़ने में बहुत तेज थे। मामा राधारमण, जो गंगापुर में सहायक स्टेशन मास्टर थे, के पास रहकर प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई की। दसवीं की परीक्षा कल्याण हाईस्कूल सीकर से दी। वे न केवल प्रथम श्रेणी से उतीर्ण हुए वरन् समस्त बोर्ड की परीक्षा में वे सर्वप्रथम रहे। 1937 में इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में बैठे और न केवल समस्त बोर्ड में सर्वप्रथम रहे, वरन् सब विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की। 1939 में सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर में प्रथम श्रेणी में बीए उत्तीर्ण किया। आगरा में एमए (अंग्रेजी) प्रथम वर्ष में उन्हें प्रथम श्रेणी के अंक मिले। 1941 में 25 की उम्र में बीटी करने प्रयाग गए।

दीनदयालजी 1937 में बीए की पढ़ाई के लिए कानपुर गए तब अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे के माध्यम से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आए, वहीं उनकी भेंट संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार से हुई। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जब कानपुर आए, तो उन्होंने उनको शाखा आमंत्रित कर बौद्धिक वर्ग करवाया। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने तथा संघ का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रचारक बन गए और आजीवन प्रचारक रहे। वे संघ में 1937 से 1951 तक रहे। दीनदयालजी सन् 1952 में जनसंघ के अखिल भारतीय महामंत्री बने। 1968 तक 16 वर्ष इस दायित्व को संभाला।

दीनदयालजी स्वाध्यायी प्रवृत्ति थे। जब भी समय मिलता लिखते–पढ़ते रहते थे। दीनदयालजी सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में मूल्यों का परिष्कार किया। दीनदयालजी गांव–गांव तक प्रचार करते थे। ज्यादातर रेलगाड़ी में सफर करते थे। ऐसा इसलिए कि एक तो उन्हें पढ़ने–लिखने का समय मिलता था और स्टेशनों पर कार्यकर्ताओं से भेंट हो जाती थी। दीनदयालजी की कुशल संगठन क्षमता से प्रभावित होकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कहा था, ''यदि मुझे दीनदयालजी जैसे चार–पांच लोग मिल जाएं, तो मैं पूरे देश में जनसंघ को खड़ा कर लूंगा।'

दीनदयालजी का कहना था कि हमारी संस्कृति और परंपरा में दुनिया को देने योग्य क्या-क्या बातें हैं, उन्हें जानें और विश्व की प्रगति में अपना सहयोग दें। लंबे अरसे तक हमारा सारा ध्यान स्वाधीनता संग्राम व आत्मरक्षा में लगा रहा। अतः हम दुनिया के अन्य राष्ट्रों की बराबरी में खड़े नहीं हो सके हैं, पर आज जब हम स्वतंत्र हैं, तो हमें इस कमी को पूरा करना होगा।

11 फरवरी 1968 के मनहूस दिन दीनदयालजी हमसे विदा हो गए। उनका शव मुगलसराय में पाया गया। संसद में प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शोक प्रस्ताव पारित नहीं होता, जिसका संसद से कोई नाता ना रहे। दीनदयालजी जी ऐसे गिने चुने उन लोगों में रहे जिनके प्रति संसद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ■

‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान का शुभारंभ

‘स्वच्छता का आंदोलन अब एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचा है’

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में राष्ट्रव्यापी भागीदारी को बढ़ावा देने एवं बापू के एक स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए 15 सितंबर को ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान आरंभ किया।

‘स्वच्छता ही सेवा‘ अभियान का उद्देश्य स्वच्छता की दिशा में अधिक सार्वजनिक भागीदारी सृजित करना है। इसका आयोजन 02 अक्टूबर, 2018 को स्वच्छ भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ की तैयारी के सिलसिले में किया जा रहा है, जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोहों के आरंभ को भी चिन्हित करेगा। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति से इस अभियान का हिस्सा बनने और एक ‘स्वच्छ भारत’ के निर्माण के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने की अपील की है। उन्होंने पूरे देश के 17 स्थानों के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ वीडियो कांफ्रेस के द्वारा बातचीत की।

बातचीत आरंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि चार वर्ष पहले जो अभियान शुरू हुआ, स्वच्छता का आंदोलन अब एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचा है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्र का हर तबका, हर संप्रदाय, हर जाति, हर उम्र के मेरे साथी इस महाअभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव हो, गली हो, नुक्कड़ हो, शहर हो कोई भी इस अभियान अछूता नहीं है।

श्री मोदी ने कुछ प्रमुख उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि किस प्रकार चार वर्षों के भीतर ही भारत के 450 जिले खुले में शौचालय से मुक्त (ओडीएफ) बन गए हैं। इसी प्रकार, 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस अवधि के दौरान खुद को ओडीएफ घोषित कर लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शौचालय या कूड़ादान जैसी सुविधाएं प्रदान करना पर्याप्त नहीं है और यह भी कहा कि स्वच्छता एक आदत है जिसे मन में बिठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश भर के लोग अब इस आदत के विकास में भागीदारी कर रहे हैं।

असम के डिब्रुगढ़ के बच्चों ने प्रधानमंत्री को अपने स्कूल एवं क्षेत्र को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपने योगदान के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने नोट किया कि युवा सामाजिक बदलाव के राजदूत हैं।

प्रधानमंत्री ने दिल्ली के एक विद्यालय में श्रमदान किया

पूरे देश के 17 स्थानों के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ वीडियो कांफ्रेस संवाद के द्वारा अभियान आरंभ करने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री मध्य दिल्ली के रानी झांसी मार्ग स्थित बाबा साहेब अंबेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की एक प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की और स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने विद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत भी की तथा उन्हें स्वच्छता के प्रयोजन की दिशा में प्रेरित किया। विदित हो कि डॉ अंबेडकर ने 1946 में अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए खुद इस स्कूल परिसर को खरीदा था।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हैदराबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हैदराबाद के डोमालगुडा के भीमा मैदान सड़क पर स्थित एनटीआर स्टेडियम में सफाई की। केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में सफाई की। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के वसंत विहार क्षेत्र में सफाई की। केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की सफाई की। असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह के साथ मिलकर गुवाहाटी में सफाई की।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बच्चों ने स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाया है, वह सराहनीय है।

गुजरात के मेहसाणा में दूध एवं कृषि सहकारी संघों के सदस्य स्वच्छता की दिशा में अपनी पहलों के बारे में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए एकत्र हुए।

मुंबई के गेट वे ऑफ इंडिया से फिल्म कलाकार अमिताभ बच्चन ने विभिन्न स्वच्छता कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी जिनसे वह जुड़े हुए हैं। विख्यात उद्योगपति श्री रतन टाटा भी इस बातचीत में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि निजी क्षेत्र स्वच्छ भारत के सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मीडिया से जुड़े व्यक्तियों, आईटीबीपी के जवानों ने भी बातचीत में भाग लिया।

छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा एवं तमिलनाडु के सलेम की महिला स्वच्छताग्रहियों ने प्रधानमंत्री को स्वच्छता की दिशा में अपने प्रयासों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने गंगा को स्वच्छ करने में जुटे स्वयंसेवकों से भी बातचीत की।

अजमेर शरीफ दरगाह के भक्तों एवं हरियाणा के रेवाड़ी के रेल कर्मचारियों ने भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। मां अमृतानंदमयी ने बातचीत में कोवलम से हिस्सा लिया।

संक्षेप में, संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छताग्रहियों की भूमिका की सराहना की और कहा कि इतिहास में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की दिशा में हमारा विश्वास और संकल्प आकाश की बुलंदियों पर है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए काम करने का आह्वान किया। ■

प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका इसे सेवा दिवस के तौर मनाना ही है

अमित शाह

आज हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और देश सेवा के लिए उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।

मैं जब से नरेंद्र भाई को जानता हूं, उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। उनके लिए यह दिन रोज के किसी भी दिन के समान होता है। आज भी वो गुजरात में हैं और सरदार सरोवर बांध राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। यह परियोजना लाखों किसानों को लाभ पहुंचाएगी। साथ ही वो स्टेचू ऑफ यूनिटी परियोजना की समीक्षा करेंगे, दाभोई में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और अमरेली में सहकारी क्षेत्र के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि आज के दिन को विभिन्न क्षेत्रों के लोग सेवा दिवस के तौर पर मना रहे हैं। कई संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं, विशेषतौर पर युवाओं द्वारा संचालित संगठन आज के दिन सामाजिक सेवाओं के प्रयासों का शुभारंभ कर रहे हैं।

नरेंद्र भाई के जन्मदिन को मनाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका इसे सेवा दिवस के तौर पर मनाना ही है। नरेंद्र भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हृदय सदैव गरीबों, समाज के वंचित वर्ग और किसानों के लिए धड़कता रहा है। उनके कल्याण की दिल की गहराई से चिंता करने के भाव ने ही उन्हें अपने युवा काल से राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित किया। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उन्होंने इंडिया फर्स्ट के भाव के साथ जिया है।

नरेंद्र भाई में देश की जनता एक प्रेम और करुणा से भरा नेता देखती है, जिसके साथ वो खुद को जोड़ती है। वे उनमें स्वयं का प्रतिबिंब देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो चौबीसो घंटे बिना किसी निजी स्वार्थ के राष्ट्र के कल्याण के काम में लगा है। उनकी लोकप्रियता सभी सीमाएं लांघ गई है।

नरेंद्र भाई का जीवन भारत को ही परिलक्षित करता है। जब नरेंद्र भाई कहते हैं कि वो गरीब के लिए ही जिएंगे और मरेंगे, तब ये उनके केवल शब्द ही नहीं है। उन्होंने गरीबी को बेहद नजदीक से देखा है और वह समझते हैं कि गरीब होने के मायने क्या हैं और वह कैसे जीता है। उन्होंने गरीब के जीवन के इस संघर्ष का अनुभव किया है। वह अपनी मेहनत और कड़े परिश्रम के बल पर लोगों के आशीर्वाद के साथ आज इस स्थान तक पहुंचे हैं। उनकी जीवन यात्रा इस देश के युवाओं को प्रेरणा और आत्मविश्वास से भर देती है कि हां मेरे लिये भी इस नए भारत में अनंत संभावनायें और अवसर है ।

यह नरेंद्र भाई की गरीबों की इच्छाओं के प्रति संवेदनशीलता ही है, जिसने उन्हें गरीबों के कल्याण के ऐतिहासिक प्रयासों के लिए प्रेरित किया। जनधन योजना की ऐतिहासिक सफलता ने लाखों लोगों के लिए बैंकिंग सिस्टम को खोला है। अब तक ये लोग देश के वित्तीय तंत्र से अलग थलग थे। आगे चलते हुए सरकार ने गरीबों के लिए अब तक के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की।

देश के युवाओं की रचनात्मकता, सृजनशीलता और कुछ कर दिखाने के जज्बे पर नरेन्द्रभाई का अटूट विश्वास है। मुद्रा योजना उनके इसी दृढ़ विश्वास का परिणाम है। यह हर्ष की बात है कि मुद्रा के लाभार्थियों में अधिकांश गरीब परिवारों, छोटे शहरों और ग्रामीण भारत के लोग हैं। देश के युवा को उनका संदेश स्पष्ट है-अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हो तो सरकार आपको उड़ने के लिए पंख प्रदान करेगी।

एक भ्रष्ट तंत्र गरीबों को कष्ट देता है। खासतौर पर मध्य वर्ग और उभरते हुए

मध्यवर्ग के लिए यह बेहद कष्टकारी साबित होता है। यह लोगों में सिस्टम के प्रति भरोसा भी कम करता है। नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज संभालने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि कालेधन पर एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया। तब से अब तक कालेधन के खिलाफ कई मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए नोटबंदी और बेनामी संपत्ति कानून लाने जैसे कदम उठाए गए। ईमानदार करदाता, जिनमे से अधिकांश मध्यमवर्ग से आते हैं आज संतुष्ट और गर्व महसूस करते हैं।

नरेंद्र भाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और वर्षों से चली आ रही कुछ चुनिंदा लोगों को सुविधा मिलने की परंपरा समाप्त हुई है। गरीबों को अब उनका अधिकार मिल रहा है। नरेंद्र भाई से अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की ताकत कहां से मिलती है। तब वह अपने ही अंदाज में कहते हैं – मैं यहां गरीब के लिए काम कर रहा हूं। मैं किसी से क्यों डरूं। यह राष्ट्र ही मेरा परिवार है। मैं यहां अपनी किसी विरासत को मजबूत करने के लिए नहीं हूं, मैं केवल और केवल भारत के लिए काम करूंगा।

किसी काम को करने की प्रतिबद्धता नरेंद्र भाई की सबसे बड़ी खूबी है। अगर कोई चीज देश के लिए अच्छी है तो वह उसे पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे ले जाते हैं। उनकी यह प्रतिबद्धता और निश्चितता भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देखी जा सकती है। सरकार ने आंतकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए हैं। आतंकवादियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत कितना सक्षम है। कूटनीतिक तौर पर भी आज नरेंद्र भाई आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के देशों का समर्थन भारत के पक्ष में लाने में सफल रहे हैं।

भारत सरदार पटेल को देश को एक सूत्र में बांधने के लिए सदैव याद करेगा। साथ ही डा. बाबा साहेब आंबेडकर को समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इसी तरह जनधन से लेकर जीएसटी तक नरेंद्र भाई ने देश को आर्थिक एकता के सूत्र में पिरोने के काम की शुरुआत की है।

किसी भी कार्य को आगे ले जाने का दिशा बोध, उसको करने की अदम्य इच्छा शक्ति और उसकी हर बारीकी की गहराई में जाने का स्वभाव उनको एक आदर्श संगठक बनाता है। दूरदराज के क्षेत्रों में संगठन का कार्य, पार्टी के प्रवक्ता या महासचिव पद तक ऐसा कोई काम नहीं है, जहां नरेंद्र भाई ने अपनी संगठन कौशल की छाप नहीं छोड़ी हो। अपने विस्तृत सांगठनिक कामकाज के चलते वह देश के प्रत्येक जिले में रहे और देश की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष अनुभव किया।

> हम देश की सेवा में इसी तरह काम करते रहें और उन्हें भारत को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना समर्थन और सहयोग देते रहेंगे। आइए इस दिन को और आने वाले दिनों को नरेंद्र भाई के एक विशेष मिशन स्वच्छ भारत मिशन के लिए समर्पित करें। 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में अपना सक्रिय योगदान दें ताकि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा किया जा सके।

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते थे तब और दिल्ली में महासचिव के अपने कार्यकाल के दौरान और आज भी नरेंद्र भाई युवा कार्यकर्ताओं के लिये एक प्रेरणास्त्रोत रहे हैं। उन्होंने हमेशा युवा, ख़ुद के बल पर और जमीन से उठ कर आने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया और उन युवाओं में काम करने की भावना को पोषित किया, न कि सत्ता में आने की भावना को। उन्होंने युवाओं को हमेशा कहा कि कुछ बनने की चाह नहीं, बल्कि कुछ करने की चाह पैदा करो।

नरेंद्र भाई से मेरी पहली मुलाकात एक युवा बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में हुई। उस वक्त भाजपा देश में उभरने का प्रयास कर रही थी। हममे से कोई भी सत्ता की तरफ नहीं देख रहा था। सत्ता हमारे लिए कोई विषय ही नहीं था। हमारा तो प्रत्येक क्षण केवल भारत के कल्याण के प्रति समर्पित था। बाद में 1995 और 1998 के गुजरात चुनाव के दौरान और पार्टी के अन्य मंचों पर मुझे नरेंद्र भाई के नजदीक रहकर काम करने का मौका मिला। यही नहीं मुझे सात साल तक नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका भी मिला। यही वक्त था जब मैंने उनकी प्रशासन पर पकड़ का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उन्होंने कैसे पूरे गुजरात को एक आदर्श राज्य के तौर पर सुशासन के साथ विकसित किया, इसका भी मैं गवाह रहा हूं।

एक बार फिर मैं अपने समस्त देशवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार के साथ नरेंद्र भाई को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम देश की सेवा में इसी तरह काम करते रहें और उन्हें भारत को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना समर्थन और सहयोग देते रहेंगे। आइए इस दिन को और आने वाले दिनों को नरेंद्र भाई के एक विशेष मिशन स्वच्छ भारत मिशन के लिए समर्पित करें। 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में अपना सक्रिय योगदान दें ताकि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा किया जा सके।

मेरा आप सभी से अनुरोध है कि स्वच्छता के प्रयासों में सक्रियता और उत्साह से शामिल हों और अपने प्रयास की फोटो नरेंद्र मोदी मोबाइल एप पर साझा करें। ताकि दूसरे लोग भी आपके कामों को देखकर प्रेरणा लें ।

वंदे मातरम ■

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा कार्य

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक देश भर में स्वच्छता अभियान चला कर कूड़ा कचरा उठाया, अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरित किया, नरेन्द्र मोदी जी के बचपन पर आधारित फिल्म भी दिखाए।

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। कीर्ति नगर की सेवा बस्ती, जवाहर कैंप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विनय सहस्रबुद्धे, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी एवं प्रदेश महामंत्री श्री राजेश भाटिया ने 17 सितंबर को स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में बस्ती के कुछ लोगों को तुलसी के पौधे भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रमों का संयोजन प्रदेश महामंत्री श्री राजेश भाटिया ने किया।

कार्यक्रम में उपस्थित हजारों सेवा बस्ती वासियों को संबोधित करते हुए श्री विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के ऐसे दूसरे बड़े नेता हैं, जिन्होंने पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाकर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की। इसीलिए उनके जन्मदिन पर आज हमनें इस सेवा बस्ती में श्रमदान कर स्वच्छता के संदेश को आपकी गली और आपके घर तक पहुंचाया है।

श्री सहस्रबुद्धे ने कहा ने कहा कि स्वच्छता एक आदत है जो हम सब के अंदर होनी चाहिए। अगर हम तीन आदतें डालें तो अपनी सेवा बस्ती को स्वच्छ रख सकते हैं। पहली शौच के बाद हमें अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए, दूसरी घर की सफाई करने के बाद जो कूड़ा निकलता है उसे गली में इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए और तीसरी कि हम पान खाकर गलियों में, सार्वजनिक स्थानों पर इधर-उधर न थूकें। अगर इन तीन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी सेवा बस्ती स्वच्छ होगी और अगर सेवा बस्ती में स्वच्छ वातावरण होगा तो यहां के निवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों के मन में सम्मान, श्रद्धा और श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति स्नेह है तो ये संकल्प लें कि आज से हम अपनी बस्ती को स्वच्छ रखने के लिए इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखेंगे।

उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यही इच्छा है कि उनके जन्मदिन को केक काटकर नहीं, पीड़ित लोगों के दुख-दर्द बांट कर मनाया जाये। इसी क्रम में पूरी दिल्ली में 11 प्रमुख स्थानों एवं 280 मंडलों में सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

चांदनी चौक जिला के यमुना घाट के यमुना बाजार के निकट गऊशाला में राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेन्द्र यादव, करोल बाग जिला के मानकपुरा की सब्जी मंडी आर्य समाज मंदिर में राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह एवं प्रदेश महामंत्री श्री रविन्द्र गुप्ता, एम बी रोड की नार्दन बस्ती में राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल जैन, शाहदरा जिला के विश्वास नगर की भीकम सिंह कालानी के कम्युनिटी सेन्टर में

श्री जे पी नड्डा, राष्ट्रीय मंत्री श्री महेश गिरी, केशवपुरम जिला के अशोक विहार के कम्युनिटी सेन्टर में केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, आर के पुरम के कुष्ठ आश्रम में केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी, रोहिणी के सेक्टर-16 में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता, मादीपुर गांव में प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थ, लोधी कालोनी के इंदिरा झुग्गी कैम्प में सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी, आई पी एक्सटेंशन में प्रदेश महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल ने आयोजित कार्यक्रमों में सेवा कार्य किये। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री सुनील यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर दीर्घायु के लिए प्रदेश कार्यालय में हवन कर केन्द्र सरकार की उपलब्धियों की कनाट प्लेस तक विकास यात्रा निकाली। ■

'मोदीजी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र दिया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 17 सितंबर को कुवाडा, भीलवाड़ा में सोना मनोविकास केंद्र के दिव्यांग बच्चों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के साथ बातचीत भी की और उन्हें पुरस्कार देते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले उन्होंने आरसी व्यास कॉलोनी (अग्रवाल भवन के पीछे) भीलवाड़ा में भीलवाड़ा और टोंक जिले की 11 विधानसभाओं के शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से एक बार फिर से प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार बनाने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन है और हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 17 सितंबर को पूरे भारत में 'सेवा दिवस' के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता देश भर में कई जगहों पर दिव्यांग बंधुओं के बीच जाकर सेवा दिवस मना रहे हैं। कई बस्तियों में सेवा कैंप के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता जनसेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सेवा दिवस के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ताकि वे लंबे समय तक इसी तरह से राष्ट्र की सेवा करते रहें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का पूरा जीवन ही राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा है, देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने और देश को विश्वगुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए समर्पित रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परिवार प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मना रही है।

श्री शाह ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं सोना मनोविकास केंद्र में दिव्यांग बच्चों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहां आकर प्रभु से निकटता का अहसास होता है, क्योंकि ये बच्चे ईश्वर के सबसे समीप हैं। सोना मनोविकास केंद्र के संचालकों को साधुवाद देते हुए उन्होंने कहा कि यह देखकर हृदय को परम संतोष की अनुभूति होती है कि समाज में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवा की लौ को जलाए हुए हैं, उन्हें बुझने नहीं दे रहे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार जरूरतमंदों का है और इस क्रम में सबसे पहला हक़ दिव्यांग बंधुओं का है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिव्यांग बंधुओं के कल्याण एवं उनके जीवन के उत्थान के लिए कई कदम उठाये हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं सरकारी भवनों को दिव्यांग बंधुओं के लिए सुगम बनाया गया है। साथ ही, 'दिव्यांगजन जन अधिकार अधिनियम' के तहत सरकारी नौकरी में 4% और शिक्षा में 5% आरक्षण का प्रस्ताव भी मोदी सरकार ही लेकर आई। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद ही शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि हम आगे भी दिव्यांगजनों के जीवन में उजाला लाने के लिए इसी तरह निरंतर कार्य करते रहेंगे।

इससे पहले शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन केवल एक ढकोसला मात्र है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कल तक जो एक-दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे, आज वे एक-दूसरे के गले मिल रहे हैं। महागठबंधन को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि उसका नेता कौन है? उन्होंने कहा कि इन पार्टियों और इनके नेताओं के एजेंडे में देश कहीं है ही नहीं। जिनके एजेंडे में केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर जनता का वोट हड़पना हो, ऐसी पार्टियां और ऐसे नेता भला देश का विकास क्या कर पायेंगे!

श्री शाह ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीबों को सिर्फ 5 रुपये में सुबह का नाश्ता और केवल 8 रुपये में दोपहर के भोजन का प्रबंध किया है, इतना ही नहीं वसुंधरा सरकार ने राज्य के किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्ज भी माफ़ किया है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस ने 55 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, राजस्थान में भी वर्षों तक शासन किया लेकिन आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को गरीब की भूख का अहसास नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने गरीबों के लिए केंद्र सरकार के अलावे 35 लाख और घरों का निर्माण किया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे अपार जन-समर्थन से यह निश्चित है कि राजस्थान में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है। ■

'स्वच्छ भारत' मिशन ने कैसे बदली भारत की तस्वीर और बना वैश्विक प्रेरणा

स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के बाद ग्रामीण भारत का स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत से बढ़कर आज 93% प्रतिशत हो गया है।

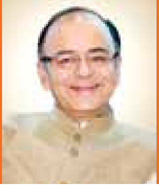

अरुण जेटली

जॉन एफ केनेडी ने जब साल 1961 में यह घोषणा की थी कि इस दशक के अंत में अमेरिका चंद्रमा पर इंसान को भेजेगा, तो उसकी बात का शायद ही किसी ने यकीन किया होगा, लेकिन ऐसा हुआ और वह भी केवल आठ वर्षों के अंतराल में। वहीं, जब खुले में शौच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में घोषणा कर कहा कि भारत साल 2019 तक खुले में शौच मुक्त देश हो जाएगा, जिसमें बड़ी समस्या उन 60 करोड़ लोगों के व्यवहार को बदलना था, जो खुले शौच जाने को मजबूर थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह संभव होगा। लेकिन चार साल बाद आज भारत खुले में शौच से छुटकारा पाने की दहलीज पर खड़ा है।

जब एक मजबूत नेता कभी-कभी एक बड़ा, कठिन, और असंभव प्रतीत होने वाला लक्ष्य रखता है, तो लोग और संस्थान उसकी पूर्ति के लिए अपने बेहतरीन प्रयास करते है। यह उन्हें उनकी सुविधावादी प्रवृत्ति से बाहर रखता है और उन्हें बड़ी सोच और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह उन्हें अपनी कल्पना की सीमाओं को बढ़ाने में भी सहयोगी होता है और इस क्रम में हर व्यक्ति अपने वेतन ग्रेड से अधिक काम करता है, अपनी क्षमताओं से अधिक प्रयास करता है और उम्मीद से बढ़कर फल प्राप्त होता है।

इस लेख को पढ़ने वाले लगभग सभी पाठकों ने कभी भी खुले में शौच नहीं किया होगा। यह बात हमारी कल्पना से परे है कि साल 2014 तक हमारे देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या खुले में शौच करने के दंश को झेल रही थी। स्वतंत्रता के 67 साल बाद भी इतनी बड़ी जनसंख्या की अवहेलना बेहद चिंताजनक स्थिति थी। लाखों लोगों की सोच में अमूमन शौचालय को कोई तर्जी नहीं दी जाती थी। महिलाओं को शौचालय की अवश्यकता थी, लेकिन वह अपनी बात को दृढ़ता से रखने में कामयाब नहीं हुई, और इसके बजाय अक्सर घरों में टेलीविजन सेट या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए महिलाओं की इस जरूरत का त्याग किया जाता रहा। इस विशालकाय समस्या को वास्तव में कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला तो लाल किले के प्राचीर से इस अवहेलना के खिलाफ हुंकार भरी। वह अभी भी विभिन्न सार्वजनिक सभाओं में शौचालयों के बारे में खुलकर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रयास के कारण शौचालय के महत्व और उसकी जरूरत पर चर्चा शुरू हुई, और इस ऐतिहासिक पहल के बाद खुले में शौच के प्रश्न पर न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जाने लगी।

वित्त मंत्री के रूप में, मेरे पास विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों और क्षेत्रों के बीच संसाधन आवंटित करने का एक कठिन कार्य है। पिछले प्रशासन के विपरीत,

हमारे लिए, देश के व्यापक विकास में स्वच्छता का महत्व काफी सहज था। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को वास्तविकता बनाने के लिए, हमें इसे पर्याप्त संसाधनों प्रदान करने पड़े और यह कार्यक्रम संसाधनों के अभाव का शिकार नहीं हुआ।

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, भारत अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सड़क, बिजली और आवास के लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही स्वच्छता हमारे प्रयासों का एक अभिन्न अंग है। स्वच्छता की खराब व्यवस्था के कारण महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को लेकर चुनौती बनी रहती है और बच्चों को भी विभिन्न बीमारियों से दो—चार होना पड़ता है, जो उनके शारीरिक और पूर्ण विकास में बाधा डालती है। इससे हमारे देश के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भारत के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिस्पर्धी लाभ यानी हमारे जनसांख्यिकीय विभाजन में बाधा आती है।

इसलिए भारत ने 20 अरब डॉलर के बजटीय प्रावधानों के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिद्धता को जाहिर किया है। सभी ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों और छोटे और भूमिहीन किसानों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत 8.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। प्रधान मंत्री ने इस कार्यक्रम के तहत सफलतापूर्वक बुरे शब्द माने जाने वाले 'शौचालय और उत्सर्जन' को भारत के विकास एजेंडे के केंद्र में ला दिया है।

पिछले चार वर्षों में, 50 करोड़ से अधिक लोगों ने खुले में शौच की आदत को छोड़ दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के बाद आज ग्रामीण भारत का स्वच्छता कवरेज 39% से बढ़कर 93% हो गया है। सामान्य रूप से स्वच्छता और विशेष रूप से शौचालय, अब चर्चा का एक प्रतिबंधित विषय नहीं है। असल में, मीडिया से लेकर आम आदमी तक, अब हर कोई इस कार्यक्रम के बारे में विचार—विमर्श कर रहा है। यह विषय भी हमारी लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है और यहां तक कि बॉलीवुड शौचालयों के महत्व के बारे में बात कर रहा है!

> पिछले चार वर्षों में, 50 करोड़ से अधिक लोगों ने खुले में शौच की आदत को छोड़ दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के बाद आज ग्रामीण भारत का स्वच्छता कवरेज 39% से बढ़कर 93% हो गया है। सामान्य रूप से स्वच्छता, और विशेष रूप से शौचालय, अब चर्चा का एक प्रतिबंधित विषय नहीं है।

देश के कई हिस्सों में शौचालयों का नाम "इज्ज़त घर" रखा गया है। हमारी इस पहल का लाभ दिखाना भी शुरू हो गया है, जो स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों में भारी निवेश के हमारे फैसले को सही साबित कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत 2019 में खुले में शौच से मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर अपने तीन लाख से अधिक नागरिकों की जिंदगी को बचाने में सफल होगा। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों में पिछले वर्ष जो निवेश किया है उसका 400% प्रतिफल प्राप्त हुआ है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस सबसे साहसी और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की है, जो भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत अब खुले में शौच के खिलाफ युद्ध का वैश्विक नेतृत्व कर रहा है।

कई देश भारत के अनुभव से सीखना चाहते हैं और अपने देशों में इसी तरह के कार्यक्रमों को लागू करना चाहते हैं। इस साल 29 सितंबर और 2 अक्टूबर के बीच, भारत महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन (एमजीआईएससी) में दुनिया भर से आए करीब 50 से अधिक स्वच्छता प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा। स्वच्छ भारत मिशन की इस अविश्वसनीय यात्रा के माध्यम से भारत के अनुभवों को साझा करने के अलावा, इस सम्मेलन स्वच्छता के विषय पर अन्य देशों के अनुभवों को सीखने-समझने का एक अवसर होगा, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध है। ■

लेखक केंद्रीय वित्त मंत्री हैं

कमल संदेश अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

'आयुष्मान भारत' से 50 करोड़ से अधिक नागरिकों को होगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ

जगत प्रकाश नड्डा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को तैयार किया गया था, जिसके तहत साधारण जनमानस तक वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना अच्छी स्वास्थ्य सेवा सेवाओं का प्रसार करने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई जो इस पहल का एक अग्रणी कदम माना जा रहा है, जिसके दो प्रमुख बिंदु इस प्रकार है।

पहला, इस योजना के माध्यम से 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घरों के करीब ले जाएंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेई) है, जो गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। आयुष्मान भारत योजना को स्वास्थ्य सेवाओं में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए अभूतपूर्व पैमाने पर लागू किया जाएगा।

अगले कुछ दिनों में पीएमजेई का शुभारंभ ऐतिहासिक होगा और यह योजना भारत में 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों की पहुंच स्वास्थ्य सेवा तक सुनिश्चित करेगी, जिन्हें अब तक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और देश की विकास यात्रा से बाहर रखा गया है। यह कदम दुनिया में सबसे बड़ी लक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना साबित होगी, और 50 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवार इस योजना के माध्यम से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के प्रसार का स्तर इस बात से समझा जा सकता है कि लागू होने के बाद यह योजना यूरोप की पूरी आबादी या अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त आबादी के बराबर लोगों को लाभांवित करेगी। पीएमजेई के तहत लाभार्थी प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के हकदार होंगे।

इस योजना के तहत गरीब परिवारों को अब बीमार होने की सूरत में वित्तीय परेशानी के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वहीं इस योजना के लागू होने के बाद इन परिवारों को सूदखोरों के चंगुल और दरिद्रता के दंश से भी बचाया जा सकता हैं।

इस योजना के तहत गरीब परिवारों को अब बीमार होने की सूरत में वित्तीय परेशानी के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वहीं इस योजना के लागू होने के बाद इन परिवारों को सूदखोरों के चंगुल और दरिद्रता के दंश से भी बचाया जा सकता हैं। हाल के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च के कारण करीब 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल जा चुके है।

रोग व्यक्ति और उसके परिवार की क्षमताओं को बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिससे पूरे परिवार को अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, पीएमजेई योजना में माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल (अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व और बाद) को भी वरीयता दी गई है, ताकि गरीब परिवार सुविधाजनक इलाज के अपने सपने को साकार कर सकें। यह योजना इलाज के दौरान होने वाले खर्च

के कारण मानसिक और आर्थिक परेशानियों में कमी लाएगी। वहीं नकद और कागजी कार्रवाई से रहित यह योजना इस पूरी प्रक्रिया को सरलीकृत करने में बेहद कारगर साबित होगी।

पीएमजेई कई मायनों में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव करेगा। पहला, यह योजना हमारी सरकार की प्रतिद्धता 'सबका साथ— सबका विकास' की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं को हमारी नीतियों के केंद्र में ले आएगी, जिसके कारण यह योजना भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक बनाकर सामने आएगी।

तीसरा, यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा और द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में नए अस्पताल, क्लीनिक और नैदानिक प्रयोगशालाओं को खोलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अस्पतालों का एक उन्नत नेटवर्क निकट भविष्य में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के लिए बड़ी संख्या में नौकरियों की मांग को बढ़ाएगा। पीएमजेई एक बेहतरीन पहल साबित होगा, क्योंकि यह निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगा। चौथा, इस पहल से पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का कैडर तैयार होगा, जिनको प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) के नाम से पहचाना जाएगा। यह आरोग्य मित्र अस्पतालों में इलाज का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों के लिए सुविधा का प्राथमिक बिंदु होगा और इस प्रकार, स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, लाभार्थियों की पहचान के लिए 3 लाख से अधिक सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

> पीएमजेई योजना में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहकारी संघवाद के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक बनने की क्षमता है। इसका सफल कार्यान्वयन केंद्र और राज्यों के बीच एक ठोस साझेदारी पर आधारित होगा। के लाभ को देखते हुए अन्य राज्य भी जल्द ही इस योजना से जुड़ जाएंगे।

अंत में, पीएमजेई योजना में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहकारी संघवाद के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक बनने की क्षमता है। इसका सफल कार्यान्वयन केंद्र और राज्यों के बीच एक ठोस साझेदारी पर आधारित होगा। अब तक, 26 राज्यों ने इसके लिए केंद्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और हमें उम्मीद है कि योजना के लाभ को देखते हुए अन्य राज्य भी जल्द ही इस योजना से जुड़ जाएंगे। पीएमजेई भारतीय स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में निर्विघ्न कार्य पद्धति और विभिन्न तकनीकी दक्षताओं का भी उदाहरण बनेगी। साथ ही भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाया गया एक बड़ा कदम सबित होगी। ■

लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं

भाजपा ने त्रिपुरा में 96 प्रतिशत पंचायत सीटें निर्विरोध जीतीं

त्रिपुरा में भाजपा ने ग्राम पंचायत संस्थाओं के उपचुनाव में 96 प्रतिशत सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की। 18 सितम्बर 2018 को राज्य चुनाव आयुक्त ने पत्रकारों को बताया कि ग्राम पंचायत की 3207 सीटें, पंचायत समिति की 161 सीटें और जिला परिषद् की 18 सीटों पर उपचुनाव हेतु 1 सितम्बर को घोषणा हुई थी। इनमें से 96 प्रतिशत सीटों पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गये। अब उपचुनाव हेतु पंचायत समिति की 7 सीटें व ग्राम पंचायत की 132 सीटें ही बची हैं। शेष सीटों के लिए 11 सितम्बर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि थी और प्राप्त नामांकनों की जांच 14 सितम्बर को संपन्न हुई। नामांकन की वापसी के बाद अब विभिन्न ग्राम पंचायत संस्थाओं की 132 सीटों पर उपचुनाव हेतु 296 उम्मीदवार बचे रह जाते हैं। यह उपचुनाव 30 सितम्बर को होंगे। यह सूचना चुनाव आयुक्त ने दी।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों, जिला परिषद सीटों की सदस्यों की एक बड़ी संख्या खाली हो गई थी, उन पर हुए उपचुनाव में (95.89 प्रतिशत) 3247 पर भाजपा ने निर्विरोध जीतीं।

भाजपा प्रवक्ता श्री मृणालकांति देब ने बताया, ''हमारे लोगों ने यह सीटें निर्विरोध जीत लीं, क्योंकि विपक्ष के पास चुनाव में प्रवेश करने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं थे। उनका संगठनात्मक आधार बिखर गया था और लोगों ने उन्हें पूरी तरह अस्वीकार कर दिया।'' ■

जनजातीय समाज के समग्र विकास की अभिनव पहल

सुदर्शन भगत

यह सत्य है कि आज भी देश के जनजाति समाज के जीवन स्तर को सुधारने हेतु बहुत कुछ किया जाना शेष है। जनजाति समाज जंगलों में वास करने वाला, कम से कम संसाधनों में जीवन यापन करने वाला, हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने वाला, अत्यंत सरल और सहनशील मनोवृति वाला समाज है। अपनी श्रेष्ठ परम्पराओं और सांस्कृतिक धरोहर से संपन्न, प्रकृति के अनुसार अपनी जीवनशैली का निर्माण करने वाला प्रकृति पूजक यह समाज देश के 2-3 राज्यों को छोड़कर कमोबेस पूरे देश में अपनी भिन्न भिन्न भाषाओं, परम्पराओं, संस्कृतियों के होते हुए भी, जनजातियों की जीवनशैली के मूल में इन सभी का प्रकृति पूजक होना ही इन्हें एक समूह में जोड़ने हेतु पर्याप्त है।

महानगरों और शहरों से सामान्यतः बहुत दिनों तक दूर रहने के अपने शर्मीले स्वभाव के कारण यह समाज विकास और व्यवसायीकरण से अनेक वर्षों तक दूर रहा। जलवायु परिवर्तन और वैश्वीकरण के इस दौर में, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जनजाति समाज पिछले अनेक वर्षों से अपने विकास के प्रति सचेत होना प्रारंभ किया है। आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अपने आर्थिक संवर्धन के प्रति ध्यान देना शुरू किया। आवश्यकता महसूस होने लगी कि खेती के समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियां और वनोत्पादों का विपणन ठीक प्रकार से न होना इनके आर्थिक संवर्धन में बाधक बना हुआ था। सरकारों द्वारा कोई ठोस नीति जनजातीय समाज को केन्द्रित करके नहीं बनाई गयी थी, इनके सर्वांगीण विकास हेतु रूपरेखा बनाना तो दूर की बात थी।

मैं अत्यंत ख़ुशी और गर्व के साथ आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय का अलग से गठन किया, जिससे कि जनजातीय समाज के समग्र विकास का विचार किया जा सके। उनके लिए ठोस नीतियां बनाई जा सकें। उन्होंने जनजातीय मानस को समझा और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया, उनके मार्गदर्शन में ही जनजाति बहुल प्रान्त छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखण्ड अस्तित्व में आये। आज इन राज्यों में भी जनजाति बहुल जिलों को केन्द्रित कर उनके विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है।

वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में जनजाति समाज के हितों और आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित कर विशेष कार्ययोजना के तहत कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वनों में रहने वाला अत्यंत सरल और सहज

जीवन जीने वाला यह समाज स्वयं को देश के विकास की मुख्यधारा से भलीभांति जोड़कर अपने बेहतर कल की ओर बढ़ सके। वह भी अपना सर्वांगीण विकास करते हुए देश के विकास में भागीदार बन सके ऐसे सकारात्मक सोच के साथ भारत सरकार देश के जनजातीय समाज के उत्थान हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। देश का जनजाति समाज, सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख है।

भारत सरकार यह चाहती है कि जनजातीय क्षेत्रों का तो विकास हो ही, साथ ही जनजातीय समाज का आर्थिक पुनरुत्थान भी तेजी से हो, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि देश के जिस ब्लाक में जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, ऐसे हर ब्लाक में 2022 तक 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' खोला जायेगा। इसलिए जनजाति शिक्षा का बजट भी बढ़ाया गया। हम हर प्रयास करके जनजातीय बालक-बालिकाओं को अच्छी शिक्षा और अच्छे अवसर प्रदान कर रहे हैं। देश के सुदूर गांव/वनों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से "आयुष्मान भारत" योजना का प्रारंभ किया गया। कैसे स्वास्थ्य सेवाएं सबको पहुंच सकें यही हमारी सरकार का प्रयास है। बेरोजगारी और पलायन से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा "स्किल इंडिया" जैसे सार्थक अभियान चलाये जा रहे हैं।

देश के जनजाति बहुल क्षेत्रों तथा ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग कैसे आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ सकें, यही हमारी सभी योजनाओं के मूल में है, जैसे मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। इस माध्यमों से आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में द्रुतगति से कार्य चल रहा है। इसके साथ ही मुझे यह बताते हुए विशेष ख़ुशी हो रही है कि गत अप्रैल माह में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के ग्राम जांगला (जिला-बीजापुर) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीद और प्रसंस्करण के लिए केन्द्र सरकार की "वन धन योजना" की घोषणा की गयी। प्रधानमंत्री जी ने कहा - देशभर में वन धन विकास केन्द्र खोले जाएंगे, ताकि हमारे वनवासी भाई-बहनों को वनोपजों का सही दाम मिल सके। साथ ही, प्रसंस्करण के जरिए उनका मूल्य संवर्धन (वेल्यू एडिएशन) किया जा सके। उन्होंने वन धन योजना के साथ-साथ "प्रधानमंत्री जन धन योजना" और "गोबर धन योजना" का भी जोरदार ढंग से जिक्र किया। मोदी जी ने कहा- ये तीनों योजनाएं ग्रामीणों और विशेष रूप से वन क्षेत्रों के निवासियों और गरीबों का आर्थिक विकास करने व उनके स्वावलंबन में मददगार होंगी।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों में खाता होने के महत्त्व को बताते हुए उन्होनें वन धन योजना के महत्व को बताया, साथ ही उदाहरण देते हुए कहा कि कच्ची इमली को जब आप बेचते हैं तो 17 रुपए या 18 रुपए प्रति किलो की कीमत मिलती है, लेकिन उसी इमली का बीज निकाल दिया जाए और बीज रहित इमली को बाजार में बेचा जाए तो उसकी कीमत 50 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो तक मिलती है। इमली बीज का मूल्य भी अलग से मिलता है, जो पौधे उगाने तथा औषधि के लिए प्रयोग होता है। इसकी कीमत भी 50 से 60 रुपये प्रति किलो होगी। उन्होंने कहा- वन धन योजना में लघु वनोपजों के संग्रहण और प्रसंस्करण के कार्यों में लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार का यह ऐतिहासिक कदम जनजातीय भाई-बहनों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लायेगा। एकलव्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर जनजातीय युवक और युवतियां जन धन योजना में खाता खुलवाकर बैंकों से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे तथा अपने ग्राम/मुहल्ले में स्वयं सहायता समूह बनाकर सहभागी प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर आय वृद्धि कर रोजगार की योजना बना सकेंगे। वे स्थानीय कृषि और वन संसाधनों को कच्चा माल के रूप में संग्रह कर उनसे जनोपयोगी, एंटिक पीस, खाद्य पदार्थ तथा बिक्री योग्य उत्पाद का उत्पादन एवं प्रसंस्करण कर सकेंगे। उन्हें प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। सरकार द्वारा उनके उत्पादों को गुणवत्ता परक बनाने और बिना बिचौलियों के संग्रह केन्द्रों और विपणन केन्द्रों पर शीघ्र बेचने और मूल्य प्राप्त करने की सुविधा दी जायगी। उन्हें अपने स्टार्ट अप तथा स्टैंड अप योजनाओं में नये हस्तशिल्प तथा उत्पाद केंद्र स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण तथा कच्चा माल सुलभ कराना, उत्पादों का संग्रह, भण्डारण, पैकिंग और सुरक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार जनजातीय युवा शीघ्र स्वावलंबी होकर रोजगार प्राप्तकर्ता से रोजगार प्रदाता बन सकेंगे।

जन धन योजना से प्राप्त ऋण तथा स्थानीय वन संसाधनों की जोड़ी (दुहरी सुविधा) का बेहतर उपयोग करके वन धन योजना पुष्पित पल्लवित होगी और जनजातीय समुदाय के शिक्षा एवं श्रम का लाभ उनके द्वार (ग्राम में) पर ही मिल सकेगा। इस प्रकार हर जनजातीय ग्राम में समृद्धि और खुशहाली आएगी।

इस प्रकार जन धन योजना से प्राप्त ऋण तथा स्थानीय वन संसाधनों की जोड़ी (दुहरी सुविधा) का बेहतर उपयोग करके वन धन योजना पुष्पित पल्लवित होगी और जनजातीय समुदाय के शिक्षा एवं श्रम का लाभ उनके द्वार (ग्राम में) पर ही मिल सकेगा। इस प्रकार हर जनजातीय ग्राम में समृद्धि और खुशहाली आएगी तथा जनजातीय समुदाय में नया आत्मविश्वास, साहस और बेहतर भविष्य की आशा बलवती होगी। यही देश की वास्तविक उन्नति का मॉडल बनेगा। ■

(लेखक केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री हैं)

भाजपा ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का एक नया विचार देश की जनता के सामने रखा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 15 सितंबर को प्रदेश भाजपा कार्यालय, नामपल्ली (हैदराबाद) में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और तेलंगाना की टीआरएस सरकार के वादाखिलाफियों और कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा तेलंगाना की जनता के साथ किये गए अन्याय को लेकर टीआरएस और कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया।

तेलंगाना की महान जनता को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का एक नया विचार देश की जनता के सामने रखा था, लेकिन शुरुआत में इसका समर्थन करने के बावजूद के. चंद्रशेखर राव एवं टीआरएस द्वारा अचानक इस पर अपना रुख बदल लेने से काफी आश्चर्य हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी 9 महीने में तेलंगाना के विधान सभा चुनाव होने ही थे, लेकिन अचानक इस निर्णय से केसीआर और टीआरएस ने एक छोटे राज्य को दो बड़े चुनावों का खर्च सहने को विवश कर दिया है। मेरा सीधा सवाल केसीआर और टीआरएस से है कि जब 9 महीने बाद यहां चुनाव होने ही थे तो आपने तेलंगाना की जनता पर इतना खर्च क्यों थोपा, इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए ही केसीआर और टीआरएस ने करोड़ों रुपये का अतिरिक्त खर्च तेलंगाना की जनता पर थोपा है। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना की टीआरएस सरकार ने राज्य पर चुनाव थोप ही दिया है, तो मैं घोषणा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर मजबूती से लड़ेगी और हम तेलंगाना में मजबूत एवं निर्णायक शक्ति बनकर उभरेंगे।

तेलुगु अस्मिता और तेलुगु गौरव पर कुठाराघात

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना में तेलुगु अस्मिता और तेलुगु गौरव की बात करने वाले लोगों ने प्रतिवर्ष 17 सितंबर को आयोजित होने वाली 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' का उत्सव बंद कर दिया। क्या हम पूछ सकते हैं कि इस उत्सव को क्यों बंद किया गया? उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम के दवाब में ओवैसी के कहने पर और वोटबैंक की पॉलिटिक्स के कारण तेलुगु संस्कृति पर कुठाराघात करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलुगु अस्मिता पर इससे बड़ा आघात कुछ और हो नहीं सकता। क्या हम आज तेलंगाना को आज के रजाकारों के हाथ में सौंपना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता को तय करना है कि क्या उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो तेलुगु अस्मिता और तेलुगु संस्कृति पर कुठाराघात कर रही है।

कांग्रेस और टीआरएस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के परिचायक

टीआरएस पर हमला जारी रखते हुए श्री शाह ने कहा कि गैर-संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यकों को अलग से 12% आरक्षण का प्रस्ताव क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, जबकि हमारा संविधान कहीं भी धर्म आधारित आरक्षण को मान्यता नहीं देता? यह उनको भी मालूम है कि धर्म आधारित आरक्षण दी नहीं जा सकती लेकिन केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए टीआरएस सरकार ने ऐसा किया है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि यदि फिर से यही सरकार तेलंगाना में चुनकर आती है तो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति और आगे बढ़ेगी।

अपने ही नेताओं का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी, कुछ वामपंथी पार्टियां और कुछ अन्य दलों ने भी मिल कर एक गठबंधन बनाया है, लेकिन कांग्रेस कैसे तेलुगु जनता के वोट पर अपना अधिकार जता सकती है, यह समझ के परे है। उन्होंने कहा कि आज भी तेलुगु जनता को याद है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह मुख्यमंत्री तन्गुतुरी अंजैया जी का अपमान किया था? तेलुगु जनता आज भी यह नहीं भूली है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेता प्रधानमंत्री श्री पीवीएल नरसिम्हा राव जी के साथ दुर्व्यवहार किया था।

टीआरएस वादों को पूरा करने में विफल

श्री शाह ने कहा कि टीआरएस सरकार पिछले विधान सभा चुनाव के समय तेलंगाना की जनता से किये गए वादों को पूरा करने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने 2014 में तेलंगाना में एक दलित मुख्यमंत्री का वादा किया था। भले ही टीआरएस इस वादे को भूल गई है, लेकिन

राज्य के दलित इसे नहीं भूले हैं। उन्होंने टीआरएस से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि भले ही आप 2014 में दलित मुख्यमंत्री के वादे को पूरा करने में आप चूक गए हों लेकिन क्या आप 2018 में इस वादे को पूरा करेंगे?

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अंधविश्वास के कारण साढ़े चार सालों तक सचिवालय न जाने का निर्णय काफी हास्यास्पद हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आंदोलन के शहीदों के शोकग्रस्त परिवारों को रोजगार देने का वादा भी आधा-अधूरा पड़ा है। शिक्षकों एवं प्रोफेसरों की नियुक्ति भी अटकी पड़ी है। सरकारी स्कूलों के लिए किये गए वादे भी पूरे नहीं हुए। सिंचाई की एक भी परियोजना की शुरुआत नहीं की गई, विरासत की योजनाओं से ही अब तक काम चलाया जा रहा है। जिला मुख्यालयों पर 100 बेड और मंडल मुख्यालयों पर 30 बेड के अस्पताल का निर्माण करने का वादा किया गया था, लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। गरीबों के लिए दो लाख डबल बेड रूम वाले घरों का निर्माण कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसमें इसे कितने डबल बेड रूम बने, किसी को इसका पता नहीं है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और गांधी अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का वादा किया गया था। उन्होंने टीआरएस सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि नए घोषणापत्र में ये वादे फिर से शामिल किये जायेंगे या नहीं, इस पर टीआरएस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने पिछले चुनाव के समय जो भी वादे तेलंगाना की जनता से किये थे, उसमें से एक को भी पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिलों का पुनर्गठन कर कई नए छोटे-छोटे जिले बनाए तो गए, लेकिन जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के बुनियादी ढांचों तक का निर्माण नहीं कराया गया।

टीआरएस ने किसानों एवं जनता की समस्याओं की अनदेखी की

श्री शाह ने कहा कि एक आंकड़े के अनुसार पिछले साढ़े चार सालों में तेलंगाना में लगभग 4,200 किसान आत्महत्या करने को विवश हुए हैं, राज्य की जनता इसका हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि खम्मम में फसल के उचित मूल्य की मांग करते किसानों को हथकड़ी पहना कर परेड करवाई गई, ऐसा स्थिति मैंने पहले कभी नहीं देखी। खैर, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश भर के किसानों को उनकी फसल पर लागत मूल्य का डेढ़ गुना या इससे भी ज्यादा समर्थन मूल्य देने का निर्णय ले लिया है, जिसे परसों की कैबिनेट मीटिंग में पास भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिरसिला जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ लड़ते हुए दलितों पर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, उसे आज भी तेलंगाना के दलित भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कल्लेश्वरम परियोजना को पूर्ण मंजूरी दी है।

कांग्रेस पार्टी जवाब दे

कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों को तेलंगाना सरकार के 12% अतिरिक्त आरक्षण के प्रस्ताव का समर्थन करती है या नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' मनायेगी? उन्होंने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस पार्टी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वह तेलंगाना का विकास नहीं कर सकती।

मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के विकास के लिए प्रतिबद्ध

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में जब सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार थी, तब 13वें वित्त आयोग में तेलंगाना को शेयर इन सेन्ट्रल टैक्स, केन्द्रीय अनुदान सहायता, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, आपदा राहत फंड और लोकल बॉडीज ग्रांट के तौर पर केवल 16,597 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में राज्य के लिए इन पांच सेक्टरों में 1,15,605 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।

श्री शाह ने कहा कि तेलंगाना में केंद्र सरकार की ओर से एम्स, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना बागवानी विश्वविद्यालय प्रो जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पी वी नरसिम्हा राव वेटरनिटी यूनिवर्सिटी दी गई है। इसके अलावे कॉटन रिसर्च सेंटर और स्पाइस रिसर्च सेंटर को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन हैदराबाद और सेंटर फॉर इनोवेशन फॉर डिफेन्स एक्सिलेंस, हैदराबाद को मान्यता दी गई है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना में मुद्रा बैंक के 18 लाख लाभार्थियों को 15 हजार करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है। स्मार्ट सिटी के लिए 124 करोड़, वारंगल हृदय योजना के लिए 40 करोड़, अमृत मिशन के लिए 833 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हैदराबाद के लिए 158 करोड़, मेट्रो के लिए 661 करोड़, अलग-अलग रेलवे परियोजनाओं के लिए 19,902 करोड़, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के लिए 1150 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के 145 प्रोजेक्ट के लिए 1221 करोड़, 9 पिछड़े जिले के विकास के लिए 900 करोड़, सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 40800 करोड़, महिला एवं बाल विकास के लिए 1055 करोड़, कृषि सिंचाई एवं पशुधन विकास के लिए 915 करोड़, उर्वरक प्लांट के लिए 5200 करोड़, मेडक NIMZ के लिए 17300 करोड़, एम्स तेलंगाना के लिए 1200 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1353 करोड़ और नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 400 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में तेलंगाना को 115000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। इस तरह से तेलंगाना को केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कुल 230000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जो कांग्रेस सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में दी गई राशि से लगभग 20 गुना अधिक है।

श्री शाह ने कहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी किस अधिकार से तेलंगाना की जनता के पास वोट मांगने जायेगी, जबकि तेलंगाना और तेलंगाना की जनता के साथ अन्याय करने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के संघीय ढांचे की भावना को मजबूत करते हुए तेलंगाना को विकास के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई जबकि राज्य में हमारी सरकार नहीं है। ■

'मोदी सरकार ने जॉब सीकर की जगह जॉब क्रियेटर बनाने का कार्य किया'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 सितंबर को पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर में जोधपुर संभाग स्तरीय युवा सम्मेलन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। इसके पश्चात् उन्होंने डॉ संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के सभागार में श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य स्मृति में आयोजित 'काव्यांजलि' कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को भी संबोधित किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा कार्यकर्ता पार्टी के भविष्य हैं, उन्हें पार्टी की परंपरा, कार्य-संस्कृति, पार्टी के मनीषी नेताओं के त्याग और देश के इतिहास को समझने और उससे सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे मनीषी तपस्वियों ने विचारधारा और सिद्धांत से समझौता न करते हुए देश के मंगल भविष्य के लिए चार पीढ़ियों तक निरंतर संघर्ष किया और इसी का परिणाम है कि 10 सदस्यों के साथ शुरू होने वाली पार्टी आज 11 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन गई है। उन्होंने कहा कि आज देश के 19 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, लगभग 1700 से अधिक विधायक हैं, लगभग 330 सांसद हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है।

> प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया जैसे कई योजनाओं को धरातल पर उतार कर युवाओं को जॉब सीकर की जगह जॉब क्रियेटर बनाने का कार्य किया है।

श्री शाह ने युवा कार्यकर्ताओं को सीख देते हुए कहा कि हमारे मनीषी नेताओं की कठिन तपस्या, अथक परिश्रम, कर्मठता और पार्टी के सिद्धांत के प्रति सच्ची निष्ठा के बगैर पार्टी के आज का वैभव की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पार्टी को आगे ले जाने और प्रधानमंत्री जी की विजय यात्रा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के कंधे पर है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में दुनिया का सबसे लोकप्रिय, परिश्रमी, प्रमाणिक और सबसे अधिक विजनरी नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है, जिनकी अगुआई में भारतीय जनता पार्टी देश के 70% भू-भागों में जनता की सेवा में अहर्निश लगी हुई है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो समझ ही नहीं आता, कभी वह जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो जाती है तो कभी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने वालों के साथ। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो कोई भी भारतवर्ष को तोड़ने का षड्यंत्र करेगा, उसे क़ानून के हिसाब से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की साजिश रचने वालों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में छोड़ा नहीं जा सकता।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया जैसे कई योजनाओं को धरातल पर उतार कर युवाओं को जॉब सीकर की जगह जॉब क्रियेटर बनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों को दलित, आदिवासी एवं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलग से ऋण उपलब्ध कराने को कहा गया है। मुद्रा बैंक योजना के तहत देश के 12 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने 'खेलो इंडिया' के माध्यम से खेल को जन-आंदोलन बनाया है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में मैडल जीत रहे हैं। मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने 3500 से अधिक युवाओं को खेलो इंडिया के तहत प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। 1000 से अधिक प्रतिभाशाली खिलाडियों को ट्रेनिंग के लिए अलग से आर्थिक सहायता दी जा रही है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पेंशन को दुगुना कर दिया गया है। गांधीनगर में पैरा एथलीट के प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाओं वाले स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है।

श्री शाह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि कई नए आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, आईटीआई और केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं। यूजीसी में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक ऐसे भारतवर्ष का निर्माण करना चाहते हैं जहां युवा विश्व के युवाओं से हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा कर सके, जहां युवाओं को अपने भविष्य को बेहतर बनाने और कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए हर सुविधा उपलब्ध हो। ■

सामाजिक न्याय और युवाओं के कल्याण हेतु हमेशा याद किया जाएगा संसद का यह मानसून सत्र: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को 'मन की बात' कार्यक्रम की 47वीं कड़ी के दौरान कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लोकसभा की उत्पादकता 118% और राज्यसभा की 74% रही। दलहित से ऊपर उठकर सभी सांसदों ने मानसून सत्र को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया और इसी का परिणाम है कि लोकसभा ने 21 विधेयक और राज्यसभा ने 14 विधेयकों को पारित किया।

श्री मोदी ने कहा कि संसद का ये मानसून सत्र सामाजिक न्याय और युवाओं के कल्याण के सत्र के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस सत्र में युवाओं और पिछड़े समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। आप सबको पता है कि दशकों से SC/ST कमीशन की तरह ही OBC कमीशन बनाने की मांग चली आ रही थी। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए देश ने इस बार OBC आयोग बनाने का संकल्प पूरा किया और उसको एक संवैधानिक अधिकार भी दिया। यह कदम सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे ले जाने वाला सिद्ध होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संशोधन विधेयक को भी पास करने का काम इस सत्र में हुआ। यह कानून SC और ST समुदाय के हितों को और अधिक सुरक्षित करेगा। साथ ही यह अपराधियों को अत्याचार करने से रोकेगा और दलित समुदायों में विश्वास भरेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश की नारी शक्ति के खिलाफ़ कोई भी सभ्य समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सज़ा का प्रावधान किया है। दुष्कर्म के दोषियों को कम-से-कम 10 वर्ष की सज़ा होगी, वहीं 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने पर फांसी की सज़ा होगी। श्री मोदी ने कहा कि यह कानून महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ़ अपराध के मामलों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभायेगा। सामाजिक बदलाव के बिना आर्थिक प्रगति अधूरी है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में तीन तलाक़ बिल को पारित कर दिया गया। हालांकि, राज्यसभा के इस सत्र में संभव नहीं हो पाया है।

मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताक़त से साथ खड़ा है। जब हम देशहित में आगे बढ़ते हैं तो ग़रीबों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मानसून सत्र में इस बार सबने मिलकर एक आदर्श प्रस्तुत कर दिखाया है। मैं देश के सभी सांसदों को सार्वजनिक रूप से आज हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 16 अगस्त को जैसे ही देश और दुनिया ने अटल जी के निधन का समाचार सुना, हर कोई शोक में डूब गया। एक ऐसे राष्ट्र नेता, जिन्होंने 14 वर्ष पहले प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। एक प्रकार से गत् 10 वर्ष से वे सक्रिय राजनीति से काफ़ी दूर चले गए थे। ख़बरों में कहीं दिखाई नहीं देते थे, सार्वजनिक रूप से नज़र नहीं आते थे। 10 साल का अन्तराल बहुत बड़ा होता है, लेकिन 16 अगस्त के बाद देश और दुनिया ने देखा कि हिन्दुस्तान के सामान्य मानवी (मानव) के मन में ये दस साल के कालखंड ने एक पल का भी अंतराल नहीं होने दिया।

श्री मोदी ने कहा कि अटल जी के लिए जिस प्रकार का स्नेह, जो श्रद्धा और जो शोक की भावना पूरे देश में उमड़ पड़ी, वो उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाती है। पिछले कई दिनों से अटल जी के उत्तम से उत्तम पहलू देश के सामने आ ही गए हैं। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं। सुशासन को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा। ■

सबको पता है कि दशकों से SC/ST कमीशन की तरह ही OBC कमीशन बनाने की मांग चली आ रही थी। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए देश ने इस बार OBC आयोग बनाने का संकल्प पूरा किया और उसको एक संवैधानिक अधिकार भी दिया।

अटलजी से जुड़ी यादों को किया साझा

गत 16 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली मासिक पुण्यतिथि के मौके पर 'अटल काव्यांजलि' कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। देशभर में लगभग 4 हजार स्थानों पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने जोधपुर (राजस्थान) में आयोजित काव्यांजलि कार्यक्रम को संबोधित किया। इन कार्यक्रमों में जहां अटलजी की कविताएं सुनाई गईं, वहीं अन्य कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाईं एवं वक्ताओं ने अपने संस्मरण सुनाए। बता दें कि 16 अगस्त को श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था।

भारतीय जनता पार्टी, नई दिल्ली जिला इकाई द्वारा 16 सितंबर को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेन्टर में 'अटल काव्यांजलि' कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया और समापन सत्र को केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने सम्बोधित किया।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी एक परोपकारी संस्कारों से पोषित व्यक्तित्व थे, जिनके विचारों को लोग राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता के बाद भी सुनते और समझते थे। उन्होंने कहा कि अटल जी विदेश नीति में भी निपुण थे। जब उनके शासनकाल में चीन ने सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग मानने से इंकार किया उस वक्त उन्होंने ऐसी कूटनीतिक विदेश नीति रखी जिसके चलते उनके 2003 के दौरे के दौरान चीन को स्वीकार करना पड़ा कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है।

श्री सिंह ने कहा कि 1999 में जब पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं में घुसने की चेष्टा की, तब अटलजी ने सेना को सख्ती से निपटने का आदेश दिया जिसके चलते भारतीय सेना पाकिस्तान को खदेड़ते हुये उसकी सीमा के अंदर वापस ले गई। परोपकारी स्वभाव के अटलजी ने सेना को पाकिस्तान में और अधिक अंदर न जाने को कहा। इसके पीछे उनका यह विश्वास था कि भारतीय सभ्यता अतिक्रमणकारी नहीं है और यह उनकी विशाल हृदयता का भी प्रमाण है।

दिल्ली प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा कि आज दिल्ली भर में ऐसे ही अटल काव्यांजलि कार्यक्रम हो रहे हैं जैसे कार्यक्रम में हम यहां डॉ. अम्बेडकर सेन्टर में उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि अटलजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और हमेशा छोटे राजनीतिक विवादों से ऊपर रहते थे। संसद में एक विपक्ष के नेता के तौर पर वह अपनी वाकपटुता एवं कविताओं से सत्ताधारी दल के सदस्यों का भी दिल जीत लेते थे। केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल ने भी अटलजी से जुड़े संस्मरणों को साझा किया।

अपने सम्बोधन में श्रीमती सुषमा स्वराज ने लगभग 1977 से अटल बिहारी वाजपेयी से प्रारम्भ हुये अपने लम्बे राजनीतिक संबंधों को की चर्चा करते हुये कहा कि चाहे सरकार में हों या विपक्ष में एक अच्छे वक्ता के रूप में वह हमेशा अपनी छाप छोड़ते थे। हम उनमें एक पिता तुल्य संरक्षक देखते थे।

उन्होंने कहा कि अटल जी को विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने-खिलाने का बहुत शोक था और विभिन्न अवसरों पर वह आने वालों को लजीज व्यंजन खिलाते थे। उनकी कवितायें जहां राष्ट्र एवं सामाजिक चिंतन से जुड़ी हैं, वहीं विभिन्न मुद्दों पर उनके निजी विचारों को भी प्रस्तुत करती हैं। श्रीमती स्वराज ने कहा कि अटल जी के जीवन में संतों के समान मानवीयता थी तो वहीं एक प्रशासक के रूप में भी उन्होंने गरीबों के लिए अपने समर्पण के चलते करोड़ों लोगों का दिल जीता। ■

सबको साथ लेकर चलता है बोहरा समाजः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को इंदौर (मध्य प्रदेश) में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के स्मरणोत्सव 'अशरा मुबारका' कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन भी उपस्थित रहे।

बोहरा समाज के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब किसी प्रवचन कार्यक्रम में कोई प्रधानमंत्री शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मगुरु सैफुद्दीन को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया है।

सैफी मस्जिद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी के बीच में आना हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, एक नया अनुभव देता है। अशरा मुबारक के इस पवित्र अवसर पर आपने मुझे बुलाया इसलिए आपका आभारी हूं। उन्होंने कहा कि बोहरा समाज ने हमेशा से शांति का पैगाम रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति का संदेश देने की यही शक्ति हमें दुनिया से अलग बनाती है, बोहरा समाज दुनिया को हमारे देश की ताकत बता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने अतीत पर गर्व है, वर्तमान पर विश्वास है। बोहरा समाज ने शांति के लिए जो योगदान दिया है, उसकी बात हमेशा मैं दुनिया के सामने करता हूं।

उन्होंने कहा कि बोहरा समाज के बीच आने से प्रेरणा मिलती है। ये समुदाय सबको साथ लेकर चलता है। उन्होंने कहा कि बोहरा समाज की भूमिका राष्ट्रभक्ति के प्रति सबसे अहम रही है। धर्मगुरु अपने प्रवचन के माध्यम से अपनी मिट्टी से मोहब्बत की बातें कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बोहरा समाज के साथ मेरा रिश्ता काफी पुराना है, मैं इस परिवार का सदस्य हूं। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि जन्मदिन से पहले ही मुझे इस पवित्र मंच से आशीर्वाद मिला है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब बोहरा समाज हमेशा मेरे साथ था। कई बार मैं धर्मगुरु जी से मिलने सूरत के एयरपोर्ट पर मिलने चला गया। श्री मोदी ने कहा कि तब मैंने उनसे गुजरात में पानी की चिंता की और उन्होंने इसके लिए तभी काम करना शुरू कर दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज बोहरा समाज कई तरह से स्वास्थ्य के लिए समाज में मदद कर रहा है। सरकार भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता कर रही है और लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने दवाईयों के दाम कम कर दिए हैं, आयुष्मान भारत के जरिए 50 करोड़ लोगों को मेडिकल की सुविधा मुफ्त में मिलेगी।

प्रधानमंत्री बोले कि अभी तक बोहरा समाज के लोगों ने करीब 11000 लोगों को अपना घर दिया है, हमारी सरकार भी 2022 तक सभी को घर देना चाहती है और हमने 1 करोड़ लोगों को घर की चाबी सौंप भी दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारा देश खुले में शौच करने से मुक्त हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि समाज के बीच से ही ऐसे लोग निकलते हैं जो धांधली को ही कारोबार मानते हैं, आप बोहरा समाज के लोग

ईमानदारी से कारोबार कर देश के लिए संदेश दे रहे हैं। हमारी सरकार की नीतियों के कारण आज देश की विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, हमारी नज़र अब जीडीपी के नंबरों को दहाई तक पहुंचाने पर है।

इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने विचार रखे। अपने वक्तव्य में धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों की प्रशंसा की। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)................................ (2)..................................

ईमेल : ....

सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :.................................... दिनांक :.............................. बैंक : ....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में विभिन्न विकास योजनाओं के शुभारम्भ के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ व उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पांडेय

नई दिल्ली में आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं से संवाद करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के लिए स्वच्छता सेवा करते और इस संदर्भ में बच्चों से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथिः (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघरः लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20